# अवध की आवाज

www.avadhkaawaz.com
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश से प्रकाशित
वर्ष–12 अंक–183 R.N.I.- UPHIN/2012/45127 लखनऊ गुरुवार 2 नवम्बर 2023 पृष्ठ – 4 मूल्य–3 रूपया

## संक्षिप्त समाचार

### विपक्षी नेताओं के मोबाइल हैकिंग दुर्भाग्यपूर्ण : रालोद

लखनऊ,(यूएनएस)। रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने विपक्षी दलों के सीनियर लीडरो के स्टेट एजेंसीज द्वारा मोबाइल हैकिंग संबंधी एप्पल कंपनी के नोटिफिकेशन को अत्यंत गंभीर एवं दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। भाजपा के शासनकाल में कुछ समय पूर्व भी इसी प्रकार से राजनयिकों एवं वरिष्ठ पत्रकारों के मोबाइल को हैक करने का प्रयास किया गया था, जिसे पेगासस कांड के नाम से जाना जाता हैं। प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण ने शीर्ष न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आर. वी. रवींद्रन द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर गौर करने के बाद इस बात का भी उल्लेख किया कि केंद्र सरकार ने पेगासस मामले की जांच में सहयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न सांसदों के मोबाइल फोन हैकिंग किए जाने का प्रयास एक तरफ जहां आम आदमी के गोपनीयता के अधिकार का हनन है, वहीं सरकार द्वारा उक्त गंभीर प्रकरण की जांच न कराकर क्लीन चिट दिया जाना केंद्र सरकार की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। राय ने कहा कि घटनाओं से स्पष्ट है कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव एवं 2024 में लोकसभा चुनाव में जनता द्वारा बुरी तरह नकारे जाने के डर से भाजपा लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास कर रही हैं ,परंतु विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भाजपा की विभाजनकारी एवं विनाशकारी नीतियों के खिलाफ करनी का फल देने को तैयार हैं।

### सड़क हादसे में दादी की मौत,नाती गंभीर घायल

बांदा। जिले में मंगलवार देर रात को अन्ना मवेशी के टकराने से बाइक में बैठे नाती और दादी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं जैसे ही स्थानीय लोगों ने देखा तो तुरंत उन्हें बबेरू सीएचसी में भर्ती कराया। जहां पर डॉक्टर के उपचार के दौरान दादी की मौत हो गई। वहीं नाती गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर हालत में नाती को बबेरू सीएचसी से बांदा ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। जहां पर युवक का उपचार किया जा रहा है। आपको बता दें की पूरा मामला बांदा के कमासिन थाना क्षेत्र अंतर्गत खरौली गांव से सामने आया है। जहां पर बाइक सवार शीला सिंह और स्वराज सिंह बबेरू से अपने घर खरौली जा रहे थे। तभी बबेरू कमासिन मार्ग में आचनक सामने से अन्ना मवेशी आ जाने की वजह से बाइक उसमें टकरा गई। जिसकी वजह से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने जैसे ही देखा तो दोनों को तुरंत बबेरू सीएचसी में भर्ती कराया। जहां पर डॉक्टर ने उपचार के दौरान शीला सिंह को मृत घोषित कर दिया। वहीं स्वराज की हालत गंभीर देखते हुए बांदा जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

## अक्टूबर में यूपी को मिली 9078.05 करोड़ की सौगात

### सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया 4484 कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण

### महिलाओं के सम्मान व स्वावलंबन पर जोर

लखनऊ, (यूएनएस)। उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेहरबान हैं। वहां भी विकास की बयार बह रही है। जहां मिशन शक्ति से महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन पर ध्यान होते हैं। वे स्वयं जनपदों में जाकर जमीनी हकीकत परखने में विश्वास करते हैं। अक्टूबर में सीएम दो दर्जन से अधिक जनपदों का दौरा किया और 9078.05 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों को गति दिया। 4484 कार्यों का कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपकर सुखद भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया। शारदीय नवरात्रि के पहले जहां मिशन शक्ति के चतुर्थ चरण का आगाज किया। कई नियुक्ति पत्र व योजनाओं की लाभार्थियों को चाबी, टैबलेट आदि देकर उन्हें

दिया तो वहीं अनेक जिलों में पहुंचकर उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ा। जनपदों में मुख्यमंत्री का यह दौरा विकास की जमीनी हकीकत से रूबरू होने वाला रहा। सभी जनपदों में समान रूप से विकास की गंगा बहाने वाले सीएम ने स्थानीय जनप्रतिनिधियो व आमजन से विकास की बातें कीं और मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा।

सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में यूपी के 80 जनपदों में समान रूप से विकास कार्य शिलान्यास–लोकार्पण कर सड़क, पेयजल, स्वच्छता, पुल आदि मूलभूत सुविधाओं को आगे बढ़ाया।सीएम योगी व्यस्तता व कार्यक्रमों के बीच भी युवाओं का ध्यान रखना न भूले। लखनऊ में 10 अक्टूबर को 394 होम्योपैथिक फार्मासिस्ट ,3 अक्टूबर को यूपी लोकसेवा आयोग द्वारा चयनित 219 प्रधानाचार्य को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में मुख्यमंत्री ने रोजगार मेले के तहत स्वरोजगार के लिए 500 करोड़ का ऋण किया वितरित, स्वावलंबन से भी जोड़ा। रामनगरी में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ किया और यहीं से महिलाओं को रोडवेज बसों में सारथी चालक के रूप में स्थापित होने में कारगर भूमिका भी निभाई। योगी सरकार के प्रयास से शक्ति की प्रतीक बेटियां इन गाड़ियों को चलाते भी दिखीं।अक्टूबर में कई जनपदों में विकास की गंगा बही।1 अक्टूबर को नैमिषारण्य में श्रमदान और 550 करोड़ से विकास कार्यों को गति,6 अक्टूबर को पीलीभीत में 26 परियोजना का लोकार्पण शिलान्यास, 248 करोड़ की दी सौगात,9 अक्टूबर को उन्नाव में 804 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण,

13 अक्टूबर को अमेठी में 700 करोड़ की 879 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण, 15 अक्टूबर को गोरखपुर नगर निगम की 189 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व 114 का लोकार्पण, 233.20 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात,

17 अक्टूबर को बुलन्दशहर में 632 करोड़ की 256 परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास,

17 अक्टूबर को हापुड़ में 136 करोड़ की 102 परियोजनाओं का लोकार्पण,शिलान्यास,19 अक्टूबर अलीगढ़ में 497 करोड़ की 208 परियोजनाओं का लोकार्पण ,शिलान्यास 19 अक्टूबर को हाथरस में 177.29 करोड़ की 214 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास,26 अक्टूबर को बागपत में 351 करोड़ की 311 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण , शिलान्यास, 28 अक्टूबर को औरैया में 688 करोड़ की 145 विकास परियोजनाओं की सौगात,28 अक्टूबर को कानपुर में 501 करोड़ की 152 विकास परियोजनाओं की सौगात, कोरथा गांव में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के बेहतर पुनर्वासन के लिए 1.56 करोड़ की वेदव्यास ग्राम विकास परियोजना का लोकार्पण,30 अक्टूबर को मीरजापुर में 202 करोड़ की 660 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण–शिलान्यास और 30 अक्टूबर को प्रयागराज में 3357 करोड़ की 424 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण–शिलान्यास किया।

## राजनाथ सिंह से मिले सिंधी समाज के लोग

### झूले लाल जयंती पर की अवकाश घोषित होने की मांग

लखनऊ,(यूएनएस)। लखनऊ में सिंधी समाज के लोगों ने आज कालिदास मार्ग स्थित आवास पर देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की। सिंधु सभा व चेटीचंड मेला कमेटी के सदस्यों ने उन्हे भगवान झूलेलाल की तस्वीर भेंटकर झूलेलाल जयंती पर उतर प्रदेश में अवकाश घोषित करने की मांग की। सभी ने कहा कि सिंधी समाज के ईष्टदेव भगवान झूलेलाल की जयंती उतर प्रदेश सहित पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है ।मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सहित देश के अन्य राज्यों में जयंती वाले दिन सार्जनिक अवकाश घोषित है। उतर प्रदेश में लागू होना करना चाहिए ।सिंधु सभा के अध्यक्ष अशोक मोतियानी, अनील बजाज, मेला कमेटी के अध्यक्ष अशोक चंदवानी, महामंत्री रत्न मेघानी, सुरेश छाबलानी, श्याम कृषनानी, हंसराज राज्यपाल,पुनीत लाल चंदानी, दीपक चांदवानी आदि ने कहा कि पाकिस्तान में हिंदू सिंधी समाज की लडकियों का खुले आम अपहरण कर धर्म परिवर्तन की खबरे मिल रही है। पर रक्षा मंत्री ने सिंधी समाज को अश्वस्त किया कि सिंधी परवारों के साथ हमेशा से ही है हर समस्या में हम पूरी मदद करेंगे। सिंधी समाज के प्रतिनिधि मंडल

सिंधी हिंदू मंदिरों को हानि पहुंचा रहे है इससे रोकने के साथ ही पकिस्तान के सिंधी हिंदुओं को सुरक्षा की मांग भी उनके समक्ष रखी गई ।सिंधु सभा के अध्यक्ष अशोक मोतियानी, सुरेश छाबलानी ने बताया की इस मौके ने रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के दौरान यह भी कहा की उत्तर प्रदेश में लॉयन ऑडर बहुत अच्छा है। सिंधी समाज सहित सभी वर्ग योगी आदित्यनाथ राज्य उत्तर प्रदेश में सुरक्षित महसूस करते है।

## राजभवन में मनाया गया लक्षद्वीप, पुडुचेरी एवं अण्डमान निकोबार द्वीप समूह का स्थापना दिवस

### समारोह में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की हुई प्रस्तुति

### शिक्षा वह है जो सर्वांगीण विकास करे : आनंदीबेन पटेल

### छात्र–छात्राएं राज्यों के भ्रमण पर जायें, कला, संस्कृति और इतिहास को जानें

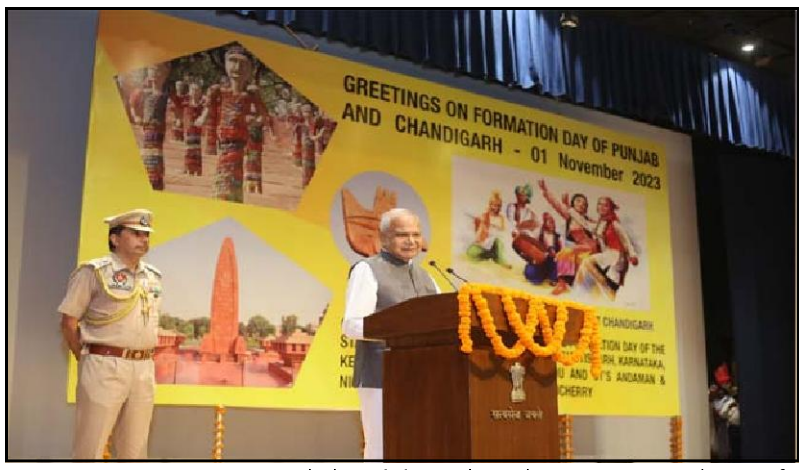


लखनऊ, (यूएनएस)। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में आज राजभवन के गांधी सभागार में 'एक भारत–श्रेष्ठ भारत' योजनांतर्गत पुडुचेरी, अण्डमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राजभवन में तीनों राज्यों की कला एवं संस्कृति को प्रदर्शित करती एक प्रदर्शनी लगायी गयी, जिसका राज्यपाल ने अवलोकन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में संस्कृति विभाग तथा उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, प्रयागराज के कलाकारों द्वारा अण्डमान निकोबार के झूमेर व निकाबारी, पुडुचेरी के गराडी तथा मिनीकॉय द्वीप के बंदिया लोकनृत्य की मनोहरी प्रस्तुति दी गयी। समारोह में तीनों केन्द्र शासित प्रदेशों पर आधारित डाक्यूमेंट्री फिल्म भी प्रदर्शित की गयी। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये राज्यपाल ने 8 राज्यों एवं 5 केन्द्र शासित प्रदेशों के स्थापना दिवस पर बधाई देते हुए लोक कलाकारों द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरण की प्रशंसा की और कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों से संवाद स्थापित करते हुए कहा कि बच्चों को भी विभिन्न राज्यों के भ्रमण पर ले जाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम प्रवास नहीं करते तब तक हमें विभिन्न राज्यों की कला एवं संस्कृति तथा रहन–सहन एवं खान–पान की जानकारी नहीं हो पाती। उन्होंने अध्यापकों से कहा कि वे बच्चों को भ्रमण के लिए प्रेरित करें और यदि किसी कारणवश भ्रमण पर न ले जा पाये तो तकनीकी का प्रयोग करते हुए उन्हें विभिन्न राज्यों की डाक्यूमेंट्री दिखाएं तथा पुस्तकों के माध्यम से चित्रांकन भी करायें। प्रयास होना चाहिए कि जब भी हम किसी क्षेत्र के भ्रमण पर जायें वहां के स्थलों को ध्यान से देखें, लिपिबद्ध करें और बच्चों को भी प्रेरित करें। राज्यपाल ने शिक्षकों तथा अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों को भ्रमण पर अवश्य ले जाएँ और वहां के संस्मरण उनसे लिपिबद्ध करायें। उन्होंने बच्चों से कहा कि आज आपने राजभवन का भ्रमण किया है। आप ने यहां जो भी अच्छा–बुरा देखा हो उसे लिखकर मुझे अवश्य भेजें। विद्यालयों में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु पठन–पाठन के साथ–साथ खेलकूद को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा वह है जो आपका सर्वांगीण विकास करे।राज्यपाल ने अण्डमान निकोबार द्वीप समूह की चर्चा करते हुए कहा कि स्वतंत्रता आन्दोलन के समय हमारे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को सेलुलर जेल में रखा गया जहां उन्हें अनेक प्रकार की यातनाएं दी गयी। उन्होंने बताया कि सेलुलर जेल में वीर सावरकर 10 साल तक रहे। जेल में यातनाएं मिलने के बाद भी वीर सेनानियों ने हमेशा भारत माता की जय का ही नारा लगाया। राज्यपाल ने बताया कि यहां समुद्र में बने कई द्वीप समूह का नामकरण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया हैसमुद्र तट पर बसे लक्षद्वीप की चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि लक्षद्वीप का प्राकृतिक वातावरण देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र है। वहां की पेयजल की व्यवस्था पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि समुद्र के खारे पानी के बीच वहां बनाये गये विशेष प्रकार के कुओं से मीठा पेय जल प्राप्त होता है।राज्यपाल ने पुडुचेरी की चर्चा करते हुए कहा कि जिस प्रकार से शान्ति निकेतन में देश–विदेश के बच्चे बड़ी संख्या में पठन–पाठन के लिए आते हैं। पुडुचेरी मेडिकल एजूकेशन का हब है। उन्होंने पुडुचेरी में स्थित ऑरेविले आश्रम को योग, आध्यात्म और साधना का केन्द्र बताया।इस अवसर पर राजभवन भ्रमण पर ज्योतिर्मठ तोटकाचार्य गुफा चमोली गढ़वा, उत्तराखण्ड हिमालय से कमलेश्वरानन्द के नेतृत्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आये 10वीं व 12वीं कक्षा के 20 टॉपर बच्चों, टीडी गर्ल्स इण्टर कालेज गोमतीनगर लखनऊ की 40 बालिकाओं ने भी राज्यों के स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया।कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव राज्यपाल डॉ सुधीर महादेव बोबडे, विशेष सचिव राज्यपाल बीएन सिंह, विधिक परामर्शी राज्यपाल प्रशांत मिश्रा, विशेष कार्याधिकारी शिक्षा पंकज जॉनी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर की कुलपति प्रो वन्दना सिंह, वाराणसी के अभिनव पेशवानी, राजभवन के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक व बच्चे उपस्थित रहे।

## महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में बनाया जाएगा सशक्त : कौशल किशोर

### लखनऊ में 31 दिसंबर को होगी "महिला सशक्तिकरण हाफ मैराथन दौड़"

लखनऊ। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री कौशल किशोर ने कहा कि महिलाओं को हर क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। आज लखनऊ के वीवीआइपी गेस्ट हाउस में मीडिया से मुखातिब मोहनलालगंज के सांसद एवं केन्द्र सरकार के राज्यमंत्री कौशल किशोर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजाद भारत में बनायी गयी नयी लोकसभा में "प्रथम नारी शक्ति वंदन अधिनियमष को भारत के संविधान में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा में 33 फीसदी आरक्षण देकर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ऐतिहासिक कार्य किया गया है, जिसके समर्थन में लखनऊ में "महिला सशक्तिकरण हाफ मैराथन दौड़" का आयोजन सभी वर्गों, सभी समुदाय के समर्थन से किया जाएगा। केंद्रीय राज्यमंत्री कौशल किशोर ने कहा कि इस महिला हाफ मैराथन दौड़ में 18 वर्ष से ऊपर की महिलाएँ शामिल हो सकती है और इसके लिए 01 नवम्बर से 15 दिसम्बर तक, 45 दिन में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती है। महिला हाफ मैराथन दौड़ में रजिस्टर्ड प्रतिभागियों को 20 दिसम्बर से 25 दिसम्बर तक चेस्ट नम्बर एलाट किए जाएँगे । महिला हाफ मैराथन दौड़ 31 दिसम्बर को दिन में 11.00 बजे शुरू होगी और यह महिला हाफ मैराथन दौड़ भी 22 किमी की होगी। महिला हाफ मैराथन दौड़ दुबग्गा चौराहा से शुरू होगी और भिटौली तिराहा होते हुए वापस दुबग्गा चौराहा पर समापन होगी। केंद्रीय राज्यमंत्री ने घोषणा की कि पुरुषों की नशामुक्त हाफ मैराथन दौड़ की तरह महिलाओं की इस हाफ मैराथन दौड़ में प्रथम विजेता को तीन लाख व द्वितीय विजेता को दो लाख व तृतीय विजेता को एक लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रथम दस में आने वाली महिलाओं को इक्कीस हजार, द्वितीय दस आने वाली महिलाओं को ग्यारह हजार, तृतीय दस आने वाली महिलाओं को एक्यावन सौ, चतुर्थ दस महिलाओं को एकतालिस सौ, पंचम दस महिलाओं को एकतीस सौ, षष्ठम् दस महिलाओं को इक्कीस सौ और सप्तम दस महिलाओं को ग्यारह सौ रुपए का प्रोत्साहन पुरस्कार, 73 महिलाओं को पुरस्कार दिए जाएँगे। प्रतिभागियों का रजिस्ट्रेशन निशुल्क है। इस नशा मुक्त हाफ मैराथन में प्रतिभाग करने के लिए 18 वर्ष के ऊपर आयु की महिलाएं रजिस्ट्रेशन लिंक www.abhiyankaushalka.org पर 01 नवंबर से 15 दिसंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं।

## एएमयू में एकता दिवस मनाया गया

अलीगढ, (यूएनएस)। अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों, स्कूलों और कार्यालयों में एकता दिवस का आयोजन जारी रहा और शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों ने भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनकी जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है।

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर युसुफुज्जमां खान ने विभाग में शिक्षकों और छात्रों को एकता की शपथ दिलाई, जबकि रेडियो–डायग्नोसिस विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर इब्ने अहमद ने अन्य संकाय सदस्यों और कर्मचारियों के साथ एकता और अखंडता की रक्षा और बढ़ावा देने की शपथ ली। संस्कृत विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर एच.एस. आचार्य ने विभाग में एक समारोह में शिक्षकों और छात्रों को एकता की शपथ दिलाई, जबकि गृह विज्ञान विभाग की अध्यक्ष डॉ. सबा खान और अन्य संकाय सदस्यों और कर्मचारियों ने देश में एकता, अखंडता और सद्भाव को मजबूत करने के लिए काम करने की शपथ ली। विभाग ने छात्रों में एकता की गहरी भावना पैदा करने के लिए निबंध और नारा लेखन प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया। भूविज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर कुँवर फ्राहीम खान ने सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों को एकता शपथ दिलाई।

कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल प्रोफेसर फरहा आजमी ने शिक्षिकाओं और कर्मचारियों को एकता की शपथ दिलाई और उनसे छात्रों में राष्ट्र के प्रति अपनेपन की भावना पैदा करने और उनसे देश के विकास और बेहतरी के लिए काम करने का आग्रह किया, जैसा कि भारत सरकार द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान के माध्यम से सुझाया और प्रचारित किया गया है।

इस अभियान का उद्देश्य आम जनता में राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा करना और भावी पीढ़ी को भारत की पोषित विरासत की रक्षा के लिए प्रेरित करना है।

सेंटर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ उर्दू टीचर्स (सीपीडीयूटी, जिसे उर्दू अकादमी भी कहा जाता है) के निदेशक प्रोफेसर कमरुल हुदा फरीदी ने शिक्षकों और कर्मचारियों को एकता की शपथ दिलाई। फैसल नफीस, प्रिंसिपल, एसटीएस स्कूल और प्रोफेसर फैयाजुर रहमान, प्रोवोस्ट, आफताब हॉल ने भी अपने–अपने स्कूल और आवासीय हॉल में शपथ दिलाई।

अन्य विभागों, आवासीय हालों, स्कूलों और कार्यालयों में उनके संबंधित प्रमुखों द्वारा एकता शपथ दिलाई गई, जिन्होंने देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने और मजबूत करने के महत्व पर भी जोर दिया।

## गोवंशों में लंपी के लक्षण मिलने से मची खलबली

बांदा,(यूएनएस)। बबेरू और अतर्रा क्षेत्र में गोवंशों में लंपी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। उनके शरीर में गांठे पड़ रही हैं और बुखार व बीमार होने की वजह से गोवंश चारा और पानी भी छोड़ दे रहे हैं। कुछ की बीमारी के कारण मौत होने की जानकारी भी है। इससे पशु चिकित्सा विभाग में खलबली मची हुई। बबेरू के गांव परास में शिव प्रसाद का गोवंश बीमार चल रहा है। उसने बताया कि इलाज कराया जा रहा है। गाय के शरीर पर गांठें हैं, उसे बुखार भी आ रहा है। पशु चिकित्सा अधिकारी कुंदल कुमार ने बताया कि गोवंशों को टीके लगाए गए हैं। वहीं, अतर्रा क्षेत्र में भी कई गोवंशों में इसी प्रकार के लक्षण मिल रहे हैं। ग्राम औरहा निवासी किसान प्रेमशंकर ने बताया कि उनके भी दो गोवंशों में गांठें दिखाई दे रही हैं। मुंह से लार निकल रही है। लंपी वायरस के लक्षण लग रहे हैं। अतर्रा के मजरा निवासी प्रेम नारायण, चंद्रपाल यादव, भूरा सिंह ने कहा कि इसी तरह की बीमारी के कारण कुछ गोवंश की मौत हो गई। चिकित्सा अधिकारी डॉ. लघुचंद अहिरवार ने कहा कि फार्मासिस्ट टीम को भेजा गया है, इलाज कराया जा रहा है।

# सम्पादकीय

## धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद लोकतंत्र के लिए विनाशकारी

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हैस स्वतंत्रता के बाद से भारत के संविधान में लोकतंत्र को सर्वोपरि स्थान दिया गया हैस देश की भौगोलिक तथा जनसंख्यात्मक विशालता में कुछ तत्व सांप्रदायिक हिंसा एवं अराजकता के परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हो सकतें हैं, पर भारतीय लोकतंत्र की महानता एवं विशालता है कि इससे संवैधानिक भारतीय लोकतंत्र को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर यह तय है कि सांप्रदायिक हिंसा एवं धार्मिक कट्टरता से लोकतंत्र की अवधारणा थोड़ी दिग्भ्रमित जरूर होती है पर इसकी मजबूती ना तो पहले कम हुई है और ना ही भविष्य में होने की कोई गुंजाइश ही है। हिंसा ,विवाद किसी भी बात का कोई हल नहीं। यह लोकतंत्र के लिए एक धब्बे के समान है। किसी भी देश में लोकतंत्र की आम ध ारणा आपसी सद्भाव और समभाव को लेकर आधारभूत रचनात्मक रूप से की गई है। विश्व के शांति प्रस्तावक भारत देश में हिंसा और हिंसक आंदोलन की कोई जगह नहीं एवं यह किसी धार्मिक, सामाजिक अथवा आर्थिक असहमति का परिणाम तो कतई नहीं हो सकती है ।भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक,प्रजातांत्रिक स्वतंत्र राष्ट्र है ।वैचारिक चिंतन, प्रभुद्धता लोकतंत्र के प्रमुख अवयव होते हैं, राष्ट्र के किसी भी नीति में सहमत और असहमत होना एक सामान्य प्रक्रिया, प्रतिक्रिया हो सकती है, और आम जनमानस का किसी मुद्दे पर आप सहमत होना भी एक सामान्य बात हो सकती है पर किन्ही भी परिस्थितियों में असहमति हिंसा के रूप में कतई बर्दाश्त के योग्य नहीं होनी चाहिए, विरोध का स्वरूप राष्ट्रीय संपत्ति की बर्बादी तो किसी भी काल और खंड में स्वीकार्य नहीं है। यह राष्ट्र के लिए घातक और विकास की अवधारणा को अवरुद्ध करने वाला आत्मघाती कदम है ।आंदोलन का स्वरूप सदैव शांति पूर्वक हो तो राष्ट्र तथा आमजन के हित में ही होगा। आंदोलनकारियों को शायद यह गुमान नहीं है कि राष्ट्रीय सरकारी संपत्ति आपके द्वारा दिए गए टैक्स के रूप में रुपयों से ही निर्मित होती है, इसे नष्ट करके आप स्वयं अपनी संपत्ति का नुकसान ही कर रहे हैं। आजादी के बाद से भारत के समक्ष कई सामाजिक आर्थिक समस्याएं आई है। अक्सर सामाजिक क्षेत्र में समस्याओं ने अर्थव्यवस्था की उत्तरोत्तर प्रगति पर अवरोध खड़े किए हैंस देश की सामाजिक विषमताओं ने समाज में कई समस्याओं को जन्म दिया है एवं आर्थिक प्रगति पर विभिन्न सोपानों में लगाम लगाई है। भारतीय समाज में विषमता एवं विविधता भारत के लिए एक बड़ी समस्या बनकर सामने खड़ी है। स्वतंत्रता के पूर्व तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय समाज में विषमताएं भारत के लिए चुनौती बनकर वर्तमान में कई बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। आज जातिगत संघर्ष बढ़ गए हैं,जातिगत संघर्षों को राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने बहुत क्लिष्ट बना दिया है। राजनीति सदैव महत्वाकांक्षा के बल पर जातिगत समीकरण को नए–नए रूप तथा आयाम देती आई है और सदैव समाज में वर्ग विभेद आर्थिक विभेद कर के अपना उल्लू सीधा करना मुख्य ध्येय बन चुका है। उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग सदैव सत्ता के संघर्ष के लिए न सिर्फ एक दूसरे का परस्पर विरोध करते है बल्कि शासन प्रशासन के विरोध ा में भी सदैव खड़े पाए गए हैं। सत्ता पाने की लालसा में जातीय संघर्ष, नक्सलवाद तेजी से समाज में पनपता जा रहा है। भारतीय परिपेक्ष में आज सिर्फ जाती ही नहीं धार्मिक महत्वाकांक्षा देश के समाज के समक्ष चुनौती बन गया है। भारत में हिंदू मुस्लिम जाति संघर्ष ऐतिहासिक तौर पर अपनी जड़ें जमां चुका है, वर्तमान में मंदिर और मस्जिद के झगड़े देश में अशांत माहौल पैदा करने का एक बड़ा सबक बन चुके है ।और यही वर्ग विभेद संघर्ष भारतीय आर्थिक विकास के बीच एक बड़ा अवरोध बनकर खड़ा है। पश्चिमी विद्वान भी कहते हैं कि भारत के राष्ट्र के रूप में विकसित होने में जाति एवं धर्म ही सबसे बड़ी बाध ाएं हैं जिन्हें दूर करना सर्वाधिक कठिन कार्य है क्योंकि इसकी जड़ें भारत के स्वतंत्रता के पूर्व से देश में गहराई लिए हुए हैं। जातीय वर्ग संघर्ष और भाषाई विवाद ऐसा मुद्दा रहा है जिससे लगभग एक शताब्दी तक भारत आक्रांत रहा है। आजादी के बाद से ही भाषा विवाद को लेकर कई आंदोलन हुए खासकर दक्षिण भारत राज्यों द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने एवं देश पर हिंदी थोपे जाने के विरोध में विरोध प्रदर्शनों को प्रोत्साहित किया गया। आज भी विभिन्न राज्यों में भाषाई विवाद एक ज्वलंत एवं संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है, चाहे वह बंगाल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा और महाराष्ट्र में भी भाषाई विवाद अलग–अलग स्तर पर सतह पर पाए गए हैं। समान सिविल संहिता को लेकर बहुसंख्यक संविध ान में आक्रोश है दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदाय इसलिए डरा हुआ है कि कहीं उसकी अपनी अस्मिता एवं पहचान अस्तित्व हीन ना हो जाए। स्वतंत्रता के बाद से यह विकास की मूल धारणा थी कि पंचवर्षीय योजनाओं में वर्ग विहीन समाज में लोकतांत्रिक एवं ध र्मनिरपेक्ष तरीके से समाज का आर्थिक विकास तथा रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकेंगे। पर स्वतंत्रता के 75 साल के बाद भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में वर्ग विभेद भाषाई विवाद ने अभी भी आर्थिक विकास में कई बाधाएं उत्पन्न की है। संविधान में सदैव सकारात्मक वर्ग विभेद एवं विकास की अवध ारणा को प्रमुखता से शामिल किया गया था और पंचवर्षीय योजनाओं में भी विकास को वर्ग विभेद से अलग रखकर विकास की अवधारणा को बलवती बनाया गया है। सामाजिक आर्थिक तथा धार्मिक विविधता वाले समाज को विवादों से परे रख आर्थिक विकास की परिकल्पना एक कठिन और दुष्कर अभियान जरूर है पर असंभव नहीं है। और इसी की परिकल्पना को लेकर आजादी के पश्चात से पंचवर्षीय योजनाओं का प्रादुर्भाव सरकार ने समय–समय पर लागू किया है। विकास की अवधारणा में राष्ट्र की मुख्य धारा में समाज के पिछड़े वर्ग को शामिल कर उन्हें सम्मुख लाना होगा। यदि देश के पिछड़ा वर्ग और गरीब तबका विकास की मुख्यधारा से जुड़ता है तो गरीबी, भुखमरी, नक्सलवाद जैसे संकट अस्तित्व हीन हो जाएंगे और ऐसी समस्या धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। आवश्यकता यह है कि हमें राष्ट्रवाद को सर्वोपरि मानकर इस पर अमल करना होगा। फिर चाहे वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो या समावेशी राष्ट्रवाद हो। समाज की मुख्यधारा में राष्ट्रवाद को एक प्रमुख अस्त्र बनाकर देश की प्रगति में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भारत में आजादी के 75 वर्ष बाद भी ब्रिटिश हुकूमत की तरह गरीबी, भूखमरी ,बेरोजगारी ,नक्सलवाद, आतंकवाद, सांप्रदायिकता,भाषावाद एवं क्षेत्रीय विघटनकारी प्रवृत्तियां सर उठाये घूम रही हैं, हम इन पर अभी तक प्रभावी नियंत्रण नहीं लगा पाए हैं। हमें इन सब विसंगतियों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय नागरिकता एवं भारत राष्ट्र की विकास की अवध ारणा को राष्ट्रवाद से जोड़कर आर्थिक विकास को एक नया आयाम देना होगा,तब जाकर भारत वैश्विक स्तर पर आर्थिक रूप से मजबूत एवं आत्मनिर्भर बन सकेगा। किसी बात का विरोध हिंसा के बिगड़े स्वरूप की तरफ शासकीय संपत्ति को नष्ट करना देश हित में नहीं।

# विपक्षी नेताओं की फोन टैपिंग

महुआ मोइत्रा समेत कई बड़े नेताओं के फोन सरकार द्वारा टैप करने का विवाद एक बार फिर खड़ा हो गया है। मंगलवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में राहुल गांधी ने यह बात सामने लाई है। दरअसल प्रसिद्ध फोन निर्माता कम्पनी एप्पल का इस्तेमाल करने वाले कई ऐसे विपक्षी नेताओं को कम्पनी की ओर से ईमेल मिला है कि जिसमें चेतावनी दी गई है कि उनके फोन राज्य समर्थित हमलावर (स्टेट स्पॉंसर्ड अटैकर्स) द्वारा टैप हो रहे हैं। अनेक विपक्षी नेताओं ने इसकी पुष्टि भी की है। राहुल ने इस बारे में कहा है कि उन्हें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता और सरकार चाहे तो बेशक उनका फोन लेकर जा सकती है, परन्तु यह न केवल निजता का हनन है बल्कि लोकतंत्र में विरोध की आवाज को दबाने की भी कोशिश है जिसका विरोध किया जाना चाहिये। मंगलवार को कई विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि उन्हें अपने आईफोन है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी इस बात की पुष्टि की है कि उनका डिवाइस हैक हो रहा है या उसकी निगरानी हो रही है। ऐसे ही, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी को भी सोमवार की रात एप्पल से एक ई–मेल मिला। उसमें भी सावधान किया गया है कि उनके फोन की राज्य–प्रायोजित निगरानी की जा रही है और उनका फोन और सभी सिस्टम हैक हो रहे हैं।श वैसे कम्पनी द्वारा इस हैकिंग से निपटना मुश्किल बताया गया है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, शिवसेना (उद्धव गुट) की प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस के लोकसभा सदस्य शशि थरूर, कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा, आवाज भी उठाते रहे हैं। उनके द्वारा मोदी सरकार की आलोचना के अंतर्गत अदानी प्रमुख विषय होते ही हैं। अपने फोन की टैपिंग के एलर्ट का संदेश देने वाले ईमेल की प्रति दिखाते हुए राहुल ने यह भी कहा कि देश में मोदी के भी ऊपर अदानी हैं। हालांकि उन्होंने एक बार फिर से इस बात की घोषणा कर दी कि चाहे जो हो जाये, वे अदानी–मोदी के कथित घोटालों को उठाते रहेंगे। उल्लेखनीय है कि पहले भी भारत सरकार पर यह आरोप लग चुका है कि उसने इजरायल से पैगासस नामक जासूसी उपकरण खरीदा है जिसके जरिये देश के अनेक लोगों के फोन टैप कराये जा रहे हैं। ऐसे में जिन लोगों के नाम सामने आये थे उनमें सिर्फ विपक्षी दल के नेता ही नहीं बल्कि नितिन गडकरी जैसे कुछ उनके अपने मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी भी

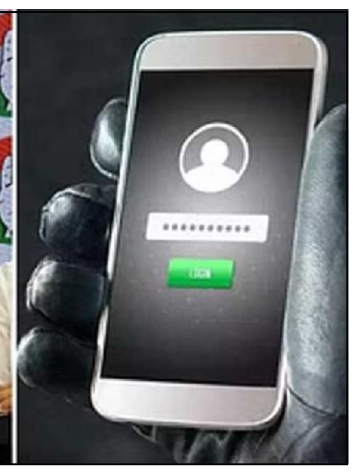

पर एक अलर्ट प्राप्त हुआ, जिसमें बताया गया है कि राज्य प्रायोजित हमलावर उनके फोन से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसकी प्रतिक्रिया में एप्पल ने कहा है कि वह खतरे से आगाह कर रही है परन्तु इसके लिये किसी भी राज्य–प्रायोजित हमलावर विशेष को जिम्मेदार नहीं ठहरा रही है। अलबत्ता उसका कहना है कि श्ऐसे हैकर्स वित्तीय रूप से बहुत अच्छे से पोषित और परिष्कृत हैं। कम्पनी के अनुसार ऐसे हमलों का पता लगाना कुछ गुप्त संकेतों पर निर्भर करता है जो ज्यादातर आधे–अधूरे होते हैं। बयान में यह भी साफ किया गया है कि संभव है कि कुछ सूचनाएं गलत चेतावनी हो सकती हैं या कुछ हमलों का पता न चल पाए।श कंपनी ने यह भी कहा है कि वह इस बारे में जानकारी देने में असमर्थ है कि किस कारण से उसे एलर्ट जारी करना पड़ा है क्योंकि इससे राज्य प्रायोजित हमलावर भविष्य में और सावधान होकर काम करेंगे। इस जानकारी के सार्वजनिक होने से हड़कम्प मच गया एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी आदि ने भी ऐसी ही चेतावनी मिलने की पुष्टि की है। कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट भी शेयर किये हैं जिसके बाद शक की गुंजाईश नहीं रह जाती है कि यह काम केन्द्र सरकार की ओर से ही हो रहा है। अब तक सरकार की ओर से कोई बयान न आना भी उसे शक के घेरे में डालता है। आखिरकार भारत के प्रतिपक्षी नेताओं के फोन टैपिंग में और किस देश की सरकार की रुचि हो सकती है?

राहुल गांधी ने इस बात को और स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कारोबारी मित्र गौतम अदानी के खिलाफ बोलने के कारण ही उनके फोन को टैप किया जा रहा है। उनकी बात में इसलिये दम दिखता है क्योंकि जितने लोगों को भी निर्माता कम्पनी द्वारा फोन टैपिंग की चेतावनी वाले ईमेल मिले हैं वे न केवल विपक्ष के हैं वरन बेहद मुखर भी हैं और अदानी के विरूद्ध थे। उनमें कुछ पत्रकार और यहां तक कि भूतपूर्व न्यायाधीश के नाम भी सामने आये थे। हालांकि उस समय भी सरकार ने इस बात से इंकार किया था कि वह किसी के फोन टैप करा रही है लेकिन उसका खुलासा जिस प्रामाणिक ढंग से हुआ था, उससे शक की कोई गुंजाईश नहीं रह जाती थी। सम्भवतया मामला उठने के बाद उतने ही गुपचुप तरीके से उसका इस्तेमाल रोक भी दिया गया होगा। हालांकि कोई इस बात को दावे के साथ नहीं कह सकता कि वह जासूसी रोक दी गई होगी।

जो भी हो, यह एक गम्भीर मसला है और सरकार को चाहिये कि इस बात की गहराई से और पारदर्शितापूर्वक जांच कर इसकी रिपोर्ट जनता के सामने लाए। हालांकि इसकी मोदी सरकार से इसकी उम्मीद करना बेकार है। सम्भव है कि सरकार इस पर मौन धारण कर ले और आतंक फैलाने हेतु यह भ्रम बनाकर रखे कि विपक्षियों के फोन टैप हो रहे हैं।

# लोकतंत्र का प्रहसन

यह अटपटा सा लगता है जब भारतीय लोकतंत्र में सबसे बड़ा कानून का अधिकारी यानी अटॉर्नी जनरल कहे कि जनता को राजनीतिक दलों के चंदे का स्रोत जानने का अधिकार नहीं है। लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा है 'जनता का शासन, जनता के द्वारा और जनता के लिये।' इस सूत्र–वाक्य से ये कहीं स्पष्ट नहीं होता है कि जनता से ऊपर राजनीतिक दलों का स्थान है। मौजूदा लोकतांत्रिक विसंगतियों व विद्रूपताओं के चलते आज स्थिति यह उत्पन्न हो गई है कि राजनीतिक दल अपने श्वेत–स्याह चंदे के स्रोतों पर जनता से परदादारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में होने वाली सुनवाई से कुछ दिन पहले अटॉर्नी जनरल ने यहां तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट को भी नीतिगत मुद्दों पर फैसला देने का अधिकार नहीं है। इसी घटनाक्रम के आलोक में यहां उल्लेखनीय है कि देश की शीर्ष अदालत ने समय–समय पर ऐसी व्यवस्थाएं दी हैं, जिससे देश में पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त हो सका है। ऐसे ही ऐतिहासिक आदेश राजनीति में दागी जनप्रतिनिधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में दिये गए हैं। उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत द्वारा वर्ष 2003 में दिये गए एक मार्गदर्शक फैसले ने हर दागी प्रत्याशी को बाध्य किया था कि वह अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि का विवरण सार्वजनिक करे। इस बाबत कोर्ट का कहना था कि यह जानना मतदाता का हक है। कमोबेश यही स्थिति चुनावी चंदा जुटाने के बाबत भी मानी जानी चाहिए। लोकतंत्र की शुचिता इस बात पर निर्भर करती है कि चुनाव की प्रक्रिया में खर्च होने वाला धन कानूनसम्मत स्रोतों से ही मिला हो। यह भी पता हो कि विभिन्न

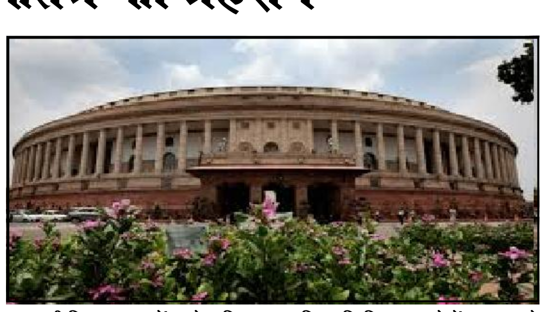

राजनीतिक दलों ने किन व्यापारिक घरानों तथा उद्योगपतियों से चंदा जुटाया है। ताकि भविष्य में सरकार बनाने पर राजनीतिक दल द्वारा चुनाव के दौरान लिये गए चंदे के एवज में जनता के हितों की कीमत पर लाभ पहुंचाने की कोशिश न की जा सके।

उल्लेखनीय है कि जब संसद में चुनावी बॉन्ड के प्रावधान को कानून का रूप देने का प्रयास किया जा रहा था तो तत्कालीन वित्तमंत्री की दलील थी कि इस कानून के अस्तित्व में आने से जहां चुनाव के लिये चंदा जुटाने में पारदर्शिता आएगी, वहीं भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाया जाएगा। लेकिन एजी के बयान से तो कम से कम वह मंशा जाहिर नहीं होती है। निस्संदेह जनता को पता होना चाहिए कि किस राजनीतिक दल ने किस कॉर्पोरेट घराने से कितना चंदा लिया है। इसमें दो राय नहीं कि कॉर्पोरेट घराने भी सत्ता की हवा भांपकर उसी अनुरूप चंदा देते हैं। एक तरह से यह उनका आर्थिक निवेश ही होता है, ताकि कालांतर लोकतंत्र में पूंजीतंत्र का पोषण हो सके। यहां उल्लेखनीय है कि चुनावी बॉन्ड को लेकर कानूनी प्रावधान है कि चंदा देने वाला व्यक्ति डिजिटल पेमेंट करके एसबीआई के बॉन्ड खरीदता है। कानून के अनुसार राजनीतिक दल व बैंक चंदा देने वाले का नाम उजागर करने के लिये बाध्य नहीं हैं। इसकी वजह से केंद्र सरकार की वित्तीय नियामक संस्थाओं को पता होता है कि कहां से चंदा आया। जिसके चलते सरकार तो जान सकती है कि विपक्षी दल के पास चंदा किस स्रोत से आया है, लेकिन विपक्ष यह नहीं जान सकता कि सरकार को कितना चंदा मिला है और किससे मिला है। जाहिर है इसका लाभ सत्तारूढ़ दल को मिलता है। साथ ही चंदे की ज्यादा मात्रा भी उसके खजाने में आती है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि सत्तारूढ़ दल को कुल चंदे का दो तिहाई हिस्सा मिला है। कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी झलकती है। बहरहाल, लोकतंत्र की शुचिता इस बात पर निर्भर करती है कि किस तरह संसाधनों से चुनावी प्रक्रिया संपन्न हुई है। जाहिरा तौर पर नियम विरुद्ध और अपवित्र स्रोत से अर्जित धन कालांतर लोकतंत्र की पवित्रता पर आंच ही लाएगा। निश्चित रूप से जनता की जागरूकता व न्यायिक सक्रियता ही चुनावी चंदे के धंधे में पारदर्शिता लाने में सक्षम हो सकती है।

# ममता बनर्जी की २५ दिनों की वो भूख हड़ताल आजतक बंगाल की आर्थिक सेहत पर भारी पड़ रही है

पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए खुद को उद्योग हितैषी दर्शाने के लिए काफी प्रयास कर रही है। ममता बनर्जी सरकार का दावा है कि राज्य में निवेश के अनुकूल माहौल है इसलिए किसी को भी मौका चूकना नहीं चाहिए। इसके लिए ममता बनर्जी की सरकार इसी नवंबर माह में 21 और 22 तारीख को कोलकाता में ग्लोबल बिजनेस समिट भी आयोजित कर रही है। इस बिजनेस समिट में देश–विदेश के निवेशक आ सकें इसके लिए खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाला हुआ है। हाल ही में ममता बनर्जी स्पेन और दुबई की 10 दिवसीय यात्रा पर भी गयी थीं ताकि निवेशकों को बंगाल में आमंत्रित किया जा सके। लेकिन इसी बीच तृणमूल कांग्रेस का उद्योग विरोधी चेहरा तब फिर सामने आ गया जब एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम को निर्देश दिया कि वह घरेलू वाहन विनिर्माता टाटा मोटर्स को सिंगूर संयंत्र में हुए नुकसान की भरपाई के लिए उसे 766 करोड़ रुपये का मुआवजा दे।

देखा जाये तो आज भले ममता बनर्जी कह रही हों कि उनकी सरकार ने राज्य में निवेश के अनुकूल माहौल बनाया है और तृणमूल कांग्रेस के शासन में बंगाल औद्योगिक विकास के मामले में आगे बढ़ा है लेकिन सच्चाई यह है कि 2006 में ममता बनर्जी ने अपनी छवि औद्योगिक विकास की विरोधी नेता की बना ली थी क्योंकि उन्होंने सिंगूर और नंदीग्राम में उद्योगों के लिए किये जा रहे भूमि अधिग्रहण का विरोध किया था। इसके नतीजतन टाटा नैनो को सिंगूर में अपनी कार परियोजना वापस लेनी पड़ी थी। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने उद्योगों को आकर्षित करने के लिए टाटा नैनो प्रोजेक्ट को गुजरात के साणंद में लगाने में मदद की और जल्द ही मोदी की छवि उद्योग जगत के बीच विकासशील नेता की बन गयी थी। हालात ऐसे हो गये थे कि बंगाल से निवेशक दूर होते जा रहे थे वहीं गुजरात में देश ही नहीं विदेशी निवेशक भी रुचि दिखा रहे थे।

देखा जाये तो टाटा नैनो के निर्माण प्लांट को पश्चिम बंगाल से बाहर भेजने के लिये दबाव डालना बड़ी भूल थी और इसने अन्य उद्योगपतियों के लिये बाधाएं पैदा करने का काम किया था। उस समय 1000 करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी टाटा मोटर्स के प्रोजेक्ट के उखड़ते दृश्य टीवी पर इतने बार दिखाये गये थे कि हर उद्योगपति ने यह बात अपने पल्ले बांध ली थी कि बंगाल में निवेश से दूर रहना है। इसलिए अब जब राज्य सरकार ग्लोबल बिजनेस समिट आयोजित करने जा रही है तब सिंगूर का भूत एक बार फिर सामने आकर खड़ा हो गया है जिसे देखकर सबके हाथ–पांव फूल रहे हैं।

ममता बनर्जी सरकार की मुश्किल यह है कि वह अब यदि जोरदार तरीके से सिंगूर आंदोलन में अपनी भूमिका का बचाव करे तो निवेशक फिर भागेंगे। राज्य सरकार यदि इस मामले पर चुप्पी साधे रहेगी तब भी उद्योगपतियों के मन से संशय के बादल नहीं छंटेंगे। वैसे भी सिंगूर आंदोलन से तृणमूल कांग्रेस पल्ला इसलिए नहीं झाड़ सकती क्योंकि इसी की बदौलत वह वामपंथियों के दशकों पुराने शासन को उखाड़ कर सत्ता हासिल कर पाई थी। लेकिन उस आंदोलन की वजह से केवल औद्योगीकरण को ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की प्रतिष्ठा को भी गंभीर नुकसान पहुंचा था। यह एक सच्चाई है कि एक समय पश्चिम बंगाल देश के बड़े औद्योगिक राज्यों में शुमार था लेकिन आज वह निवेश के लिए तरस रहा है।

जहां तक टाटा मोटर्स के पक्ष में आये फैसले की बात है तो आपको बता दें कि टाटा मोटर्स ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा है कि तीन–सदस्यीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया है। इसके मुताबिक, कंपनी प्रतिवादी पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड से 765.78 करोड़ रुपये की राशि 11 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वसूलने की हकदार है। ब्याज की गणना एक सितंबर, 2016 से मुआवजा चुकाने की तारीख तक होगी। टाटा मोटर्स ने सिंगूर संयंत्र बंद होने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड से मुआवजा मांगा था। इसमें पूंजी निवेश पर हुए नुकसान समेत अन्य मदों में दावा किया गया था।

देखा जाये तो यह फैसला राज्य सरकार के लिए बड़ा झटका है लेकिन ग्लोबल बिजनेस समिट की तैयारियों में जुटी पश्चिम बंगाल सरकार ने इस पर चुप्पी साध ली है और सत्तारुढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। तृणमूल कांग्रेस ने टाटा मोटर्स की जीत को तवज्जो नहीं देते हुए कहा है कि यह ''अंतिम फैसला नहीं है'' तथा राज्य सरकार के सामने कानूनी रास्ते खुले हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस चाहे कुछ भी कहे लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ममता सरकार को यदि सरकारी खजाने से टाटा को 766 करोड़ रुपए देने पड़े तो बड़ी मुश्किल हो जायेगी क्योंकि पहले ही गलत आर्थिक नीतियों के चलते राज्य का खजाना खाली बताया जा रहा है। दरअसल राज्य सरकार ने अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करके कभी राजस्व बढ़ाने की दिशा में सही प्रयास ही नहीं किये। यह अलग बात है कि राज्य के मंत्रियों और विधायकों के यहां अक्सर पड़ने वाले छापों के दौरान जो करोड़ों रुपए मिलते हैं वह दर्शाते हैं कि राज्य में पैसे की कोई कमी नहीं है। आज के बंगाल की यह कड़वी सच्चाई है कि भ्रष्टाचार चरम पर है, तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है और लोक लुभावन नीतियों की वजह से हो रही धन की बर्बादी के चलते राज्य पर कर्ज का भारी बोझ है। ऐसे में टाटा को 766 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का निर्देश कैसे पूरा होगा यह सवाल सबके जेहन में आना स्वाभाविक है।

बहरहाल, सिंगूर के आंदोलन ने राज्य से निवेशकों को तो दूर किया ही था साथ ही टाटा मोटर्स का प्रोजेक्ट काफी हद तक लग जाने के चलते कृषि भूमि भी उपजाऊ नहीं रह गयी थी। यही नहीं, तृणमूल कांग्रेस ने सिंगूर के लोगों से विकास और रोजगार के जो वादे किये थे, बताया जाता है कि वह अब तक पूरे नहीं हुए हैं। कुल मिलाकर देखें तो बंगाल के हाथ से एक बड़ा प्रोजेक्ट गया था, कृषि भूमि बर्बाद हो गयी थी, किसानों को जमीन तो वापस मिल गयी लेकिन सुनहरा भविष्य नहीं मिला। अब 766 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ राज्य के खजाने पर पड़ गया है। कहा जा सकता है कि 2006 में ममता बनर्जी ने कोलकाता में एस्प्लेनैड में 25 दिनों तक जो अनिश्चिकालीन भूख हड़ताल की थी उसका विपरीत असर राज्य की आर्थिक सेहत पर लगातार देखने को मिल रहा है।

# मराठा आरक्षण की आग

जब आरक्षण के प्रावधान संविध ान में जोड़े गए तब वे न तो जाति को लेकर थे न ही ध्आर्थिक पिछड़ेपन को लेकर। तब सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने की बात थी। तब यह माना गया कि आर्थिक पिछड़ापन दूर करना सरकार का फर्ज है इसलिए आरक्षण को गरीबी दूर करने का हथियार नहीं समझा गया था। बाद में वोट बैंक की राजनीति के चलते आरक्षण ऐसा अमृत का प्याला हो गया जिसे छूकर हर जाति अपनी समस्याओं को दूर करना चाहती है। इस देश ने आरक्षण आंदोलन के हिंसक दौर को एक बार नहीं कई बार देखा है। आरक्षण की आग में समाज पहले भी कई बार झुलस चुका है। चाहे वह हरियाणा के जाटों का आंदोलन हो, गुजरात में पटेल समुदाय का आंदोलन हो, राजस्थान के गुर्जर समुदाय का आंदोलन हो, आंध्र प्रदेश के कापू समुदाय का आंदोलन हो। आंदोलन जब हिंसक होते हैं तो न केवल लोगों की जानें जाती हैं बल्कि राष्ट्र की सम्पत्ति को भी नुक्सान पहुंचता है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन एक बार फिर हिंसक हो गया है। राज्य में अलग–अलग जगहों पर दो विधायकों के और एक मंत्री के घर को आग लगा दी गई। दर्जनों वाहन फूंक डाले गए। राकांपा का कार्यालय जला दिया है। बीड समेत कई जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है और कर्फ्यू लगा दिया गया है। आरक्षण की मांग को लेकर लोग आत्महत्याएं करने लगे हैं और विधायक और सांसद इस्तीफे दे रहे हैं। आंदोलन के हिंसक होने से राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार की मुसीबत और बढ़ गई है। मुख्यमंत्री शिंदे मराठा हैं। उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडण्वीस और राकांपा दिग्गज शरद पवार भी मराठा हैं। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं और उनकी अपील पर आंदोलनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। महाराष्ट्र में करीब 32 साल पहले मराठा आरक्षण को लेकर पहली बार आंदोलन हुआ था। ये आंदोलन मराठी लेबर यूनियन के नेता अन्नासाहब पाटिल की अगुवाई में हुआ था। उसके बाद से मराठा आरक्षण का मुद्दा यहां की राजनीति का हिस्सा बन गया। महाराष्ट्र में ज्यादातर समय मराठी मुख्यमंत्रियों ने ही सरकार चलाई है लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल सका। जबकि 2014 के चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठाओं को 16 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए अध यादेश लेकर आए थे लेकिन 2014 में कांग्रेस–एनसीपी गठबंधन की सरकार चुनाव हार गई और बीजेपी–शिवसेना की सरकार में देवेंद्र फड़णवीस मुख्यमंत्री बने। फड़णवीस की सरकार में मराठा आरक्षण को लेकर एमजी गायकवाड़ की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग बना। इसकी सिफारिश के आधार पर फड़णवीस सरकार ने सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एक्ट के विशेष प्रावधानों के तहत मराठाओं को आरक्षण दिया। फड़णवीस की सरकार में मराठाओं को 16 प्रतिशत आरक्षण मिला लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे कम करते हुए सरकारी नौकरियों में 13 प्रतिशत और शैक्षणिक संस्थानों में 12 प्रतिशत कर दिया। मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। दरअसल, मराठा समुदाय का कहना है कि सितंबर 1948 तक निजाम का शासन खत्म होने तक मराठाओं को कुनबी माना जाता था और ये ओबीसी थे, इसलिए फिर से इन्हें कुनबी जाति का दर्जा दिया जाए और ओबीसी में शामिल किया जाए। यह लड़ाई लंबे समय से चल रही है लेकिन ऐसा नहीं कि राज्य सरकार ने ऐसा कदम नहीं उठाया हो। महाराष्ट्र सरकार मराठाओं को आरक्षण देने की पूरी कोशिश में है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा सीमित कर रखी है, वह सरकार के लिए रोड़ा बनी हुई है। महाराष्ट्र में लगभग 30 फीसदी मराठा समुदाय की आबादी है। सामाजिक और आर्थिक रूप से यह समुदाय काफी पिछड़ा हुआ है। उच्च शिक्षा संस्थानों और नौकरियों में मराठा समुदाय का प्रतिनिधित्व न के बराबर है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एसबीसीसी) की साल 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र में करीब 37.28 फीसदी मराठा गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे रहते हैं। इस समुदाय का 76 फीसदी समुदाय कृषि और कृषि श्रम पर निर्भर करता है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि माली हालत ठीक नहीं होने की वजह से 2013 से 2018 तक 2152 मराठा समुदाय के किसानों ने आत्महत्या की। इस खुदकुशी की मुख्य वजह कर्ज और फसल की बर्बादी थी। मराठा आरक्षण आंदोलन के पीछे भी कई कारण हैं। एक मुद्दा आरक्षित वर्गों व जातियों के क्रीमी लेयर का है जो सारा फायदा लेकर जा रहा है। इससे युवाओं में नाराजगी बढ़ी है। उन्हें लगता है कि 90 फीसदी अंक लाकर भी उनका दाखिला अच्छे संस्थानों में नहीं होता, जबकि अपेक्षाकृत काफी कम अंक लाकर आरक्षण के बूते पर दूसरी जातियां लाभ उठाती हैं। अब यह पड़ताल करने का समय आ गया हैध कि आज हमारा समाज वास्तव में कितना पिछड़ा है और उसे आरक्षण की कितनी जरूरत है। अगर हम जाति युद्ध से बचना चाहते हैं तो हमारे नीति निर्माताओं को ठोस कदम उठाना होगा। एक ऐसा राष्ट्रीय आयोग बनना चाहिए जो तमाम मुद्दों को परखे और आरक्षण उन्हें ही दिया जाए जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत हो। आरक्षण का लाभ पीढ़ी दर पीढ़ी ले चुके लोगों को इससे वंचित किया जाना चाहिए। मैं इस बात का पक्षधर हूं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। यह काम वोट बैंक की राजनीति को देखते हुए न होकर ईमानदारी से किया जाना चाहिए।

# डीएम ने तालाबों का किया निरीक्षण, अधीनस्थों को दिए निर्देश, कहा- छठ पूजा से पहले हो जाये सफाई

उरई/जालौन। जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने उरई नगर का भ्रमण किया, इस दौरान तालाबों का निरीक्षण किया, जहां तालाब में गंदगीबौर नगर में साफ सफाई व्यवस्था सही से न होने पर अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिये, साथ ही कहा कि नगर में साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए, साथ ही छठ पूजा से पहले तालाबों की साफ सफाई सही से कर ली जाए, जिससे पूजा के दौरान गंदगी न मिले। डीएम को भ्रमण के दौरान कई जगहों पर कूड़े के ढेर मिले साथ ही पास में ही कूड़े में आग लगाकर जला हुआ देख नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिशासी अधिकारी को फटकार लगाई, साथ ही निर्देश दिए कि शहर में गंदगी करने, सड़क पर कूड़ा फेंकने वाले व कूड़ा करकट जलाने वालों के विरुद्ध जुर्माना के साथ–साथ दंडात्मक कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से कूड़े में आग लगाने वाले व्यक्तियों की पहचान कर कड़ी कार्यवाही की जाये, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही व शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया के प्रतिदिन सड़कों से कूड़े का समुचित जगह पर निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि दुकानों के आगे डस्टबिन रखवाई जाए जिससे निकलने वाले कूड़े को डस्टबिन में ही डाला जा सके। नगर मजिस्ट्रेट व क्षेत्राधिकारी उरई को निर्देश देते हुए कहा कि जिन दुकानदारों द्वारा गंदगी फैलाई जा रही है। नालों को चोक किया गया एवं नालों के ऊपर अतिक्रमण किया गया है। उन्हें चिन्हित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने छठ पूजा के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए माहिल तालाब व राम कुंड पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

# अंजुमन के खिलाफ साजिश नहीं उसे बचाने की कोशिश की जा रही

## किसी भी संस्था बाहर से नही बल्कि उसके भ्रष्ट पदाधिकारियों से खतरा

लखनऊ,(यूएनएस)। किसी संस्था को ना तो बदनाम किया जा सकता है न ही उसके खिलाफ कोई साजिश की जा सकती है। जब किसी संस्थान के पदाधिकारी के काले कारनामों और नापाक कोशिशों के खिलाफ मुहिम चलाकर संस्था को बचाने की कोशिश की जाती है तो उसके भ्रष्ट पदाधिकारी संस्था की बदनामी और उसके खिलाफ साजिश की बात कहकर छिपने और बचने की कोशिश करते हैं। किसी संस्था में अगर कोई भ्रष्टाचार होता है तो उस भ्रष्टघचार के लिए उस संस्था के पदाधिकारी ही दोषी होते हैं। किसी भी संस्था को बाहर वालों से नहीं बल्कि उस संस्था के भ्रष्ट पदाधिकारियों से ही खतरा होता है। पूर्व में उजरियाँव कब्रिस्तान पर मार्केट और फ्लैट आदि बनाने की योजना को लेकर अंजुमन के छोटे साहब और बड़े साहब ने मौका मुआयना भी कर लिया था। अंजुमन द्वारा संचालित अमीनाबाद स्थित इंटर कॉलेज की ग्राउंड की नाप तक की जा चुकी है। उस पर भी मार्केट बनाने की योजना थी। सर्वोदय नगर कब्रिस्तान की जमीन भी निशाने पर थी। परंतु अखबारों में खबर छपने से छोटे साहब और बड़े साहब की योजना पर पानी फिर गया। जिससे परेशान होकर बयान बाजी कर रहे हैं और उनकी योजना का पर्दा फाश करने वालों को कानूनी कार्यवाही की धमकी दे रहे हैं। कानूनी कार्यवाही की धमकी से यह संगठन डरने वाले नहीं हैं बल्कि यह साफ कर देना चाहते हैं कि यदि इन भ्रष्ट पदाधिकारी ने कब्रिस्तान व अन्य सम्पत्तियों की जमीनों पर फ्लैट या दुकान आदि बनाने की कोशिश की तो उनके खिलाफ ही सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह विचार राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता संगठन के कन्वीनर मोहम्मद आफाक और मस्जिद, मदरसा, दरगाह एवं कब्रिस्तान बचाओ समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हाजी फहीम सिद्दीकी ने अंजुमन की वक्फ संपत्तियों को बचाने के संबंध में आयोजित एक बैठक में संयुक्त रूप से व्यक्त किये। बैठक का आयोजन मस्जिद, मदरसा, दरगाह एवं कब्रिस्तान बचाओ समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हाजी फहीम सिद्दीकी ने किया। बैठक में मुख्य रूप से ऑल इंडिया मजलिस इत्तिहाद मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष डॉ. आफताब, शराबबंदी संघर्ष समिति के अध्यक्ष मुर्तजा अली, मुहम्मद अहमद, इसार फाउंडेशन के अध्यक्ष मौलाना इरशाद अहमद सिद्दीकी इंडियन नेशनल लीग के प्रवक्ता सैयद अली मुशीर जैदी, स्मार्ट पार्टी ऑफ भारत के अध्यक्ष शहजादे मंसूर अहमद, मुहम्मद मक्की एडवोकेट, तुफैल अख्तर, परवेज आलम, महमूद अली वारसी, फरीदा बेन, रोशन जहाँ, राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता संगठन के कन्वीनर मोहम्मद आफाक, मस्जिद, मदरसा, दरगाह एवं कब्रिस्तान बचाओ समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हाजी फहीम सिद्दीकी मौजूद थे। बैठक में मौजूद लोगों ने कहा कि थाना गोमती नगर में कब्रिस्तान से कब्जा हटाने का प्रार्थना पत्र देना ही उनकी नापाक योजना का हिस्सा था ताकि कब्जा खाली कराकर निर्माण कार्य शुरू करने की कार्य योजना पर अमल के लिए आगे बढ़ा जा सके। मगर कुछ सामाजिक संगठनों के संयुक्त प्रयास और अखबारों में खबर छप जाने की वजह से उनकी इस नापाक योजना पर पानी फिर गया। अंजुमन के एक पदाधिकारी को यह स्पष्टीकरण देना पड़ गया और घोषणा करनी पड़ी कि कब्रिस्तान व अन्य संपत्तियों पर कोई निर्माण नहीं कराया जाएगा। यह अंजुमन और उसकी संपत्तियों को बचाने की राह में एक बड़ी कामयाबी है। अंजुमन के ईमानदार लोगों से इस तरह की योजनाओं को छुपाया जा रहा है और उन्हें गुमराह किया जा रहा है। अंजुमन के ईमानदार पदाधिकारी को अंजुमन के कार्यों से दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है। हम अंजुमन के पदाधिकारी से अपील करते हैं कि वह इस तरह की कार्यवाहियों पर कड़ी नजर रखें क्योंकि कब्रिस्तानों आदि की रक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है।

# डीएम ने की समीक्षा बैठक, सबसे खराब उपलब्धि वाली आशा-एएनएम को बर्खास्त करने के निर्देश

बस्ती। जिलाधिकारी आद्रवामसी ने कलक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सप्ताह में दो पीएचसी और छह हेल्थ वेलनेस सेंटर का निरीक्षण कर रिपोर्ट भेजे। सबसे खराब उपलब्धि वाली चार–चार आशा व एएनम को चिह्नित करें और उनकी बर्खास्तगी की कार्यवाही करें। कायाकल्प योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने पाया कि बालक– बालिकाओं व दिव्यांग टॉयलेट के निर्माण की प्रगति धीमी है। टायलटीकरण का कार्य भी अपेक्षित गति से नहीं संचालित है। इसके लिए उन्होंने सभी सहायक विकास अधिकारी पंचायत को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है।

मतदाता पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा करते हुए डीएम ने निर्देश दिया कि सभी सहायक मतदाता रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जेंडर रेशियो बढ़ाने के लिए कार्य करें। महिलाओं और बालिकाओं का अधिक से अधिक फॉर्म 6 भरवाया जाए। 24 साल से अधिक आयु के व्यक्ति को मतदाता बनाने के लिए फॉर्म 8 भरवाया जाए। उन्होंने मृतक, शिफ्टेड लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाने का भी निर्देश दिया है। विशेष रूप से उन्होंने 18 से 19 वर्ष आयु के नए मतदाताओं की संख्या बढ़ाने पर बल दिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि ग्राम समाज की भूमि पर किसी भी दशा में अवैध अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, इसमें संलिप्त लेखपाल के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने आयुष्मान गोल्डनकार्ड व प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों का ईकेवाईसी 10 दिन में पूरा करने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने कायाकल्प योजना के तहत विद्यालयों का कार्य अपूर्ण पाए जाने पर असंतोष व्यक्त किया, सभी सहायक विकास अधिकारी पंचायत को निर्देशित किया कि वे एबीएसए के साथ स्कूलों का भ्रमण करके सभी कार्य पूर्ण कराएं। बैठक में सीडीओ जयदेव सीएस, एडीएम कमलेश चंद, सीएमओ डॉ. रमाशंकर दुबे, उप जिलाधिकारी गुलाबचंद, विनोद पांडे, शत्रुघ्न पाठक, आशुतोष तिवारी, डिप्टी कलेक्टर रमेश यादव, डीडीओ निर्मल द्विवेदी, बीएसए अनूप कुमार आदि मौजूद रहे।

# 'ई-सामग्री विकास' पर दो दिवसीय कार्यशाला का समापन

अलीगढ़। अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कंप्यूटर विज्ञान विभाग के सहयोग से यूनानी चिकित्सा संकाय द्वारा 'ई–सामग्री विकास' पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला संपन्न हो गयी। कार्यशाला का उद्देश्य व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना था। शिक्षकों और शोधार्थियों सहित 80 प्रतिभागियों ने कार्यशाला में भाग लिया। मुख्य अतिथि कंप्यूटर विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर आसिम जफर ने कार्यशाला की थीम और आयोजक टीम के प्रयासों की सराहना की। डॉ. अम्मार इब्ने अनवार ने धन्यवाद ज्ञापित किया। उद्‌घाटन समारोह में मनाफउल आजा विभाग के अध्यक्ष और कार्यशाला के आयोजन सचिव डॉ. फारूक अहमद डार ने कार्यशाला के उद्देश्यों को रेखांकित किया।

यूनानी चिकित्सा संकाय के डीन प्रो. उबैदुल्ला खान ने ई–कंटेंट और व्यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) विकसित करने के महत्व पर जोर दिया। अजमल खान तिब्बिया कॉलेज के प्रिंसिपल प्रो. बी.डी. खान ने ई–सामग्री विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यशाला के दौरान, प्रतिभागियों ने मूक्स, स्वेयम, उन्नत पीपीटी उपकरण, ओबीएस और वीएसडीसी सॉफ्टवेयर सहित विभिन्न ई–सामग्री विकास विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रोफेसर आसिम जफर ने फंडिंग के रास्ते और ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज (ओईआर) और स्वेयम, ईडीएक्स और कौरसेरा जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के महत्व पर चर्चा की। डॉ. यूसुफ अंसारी ने उन्नत पीपीटी उपकरण और एनीमेशन तकनीकों का प्रदर्शन किया। डॉ. फैसल अनवर ने ओबीएस, वीएसडीसी और वीडियो संपादन टूल पर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया। डॉ. एम. नदीम खान और डॉ. हाफिज इक्तिदार अहमद ने कार्यशाला समन्वयक के रूप में कार्य किया। इस कार्यक्रम में ई–सामग्री विकास में नवीनतम रुझानों और प्रौद्योगिकियों में जानकारी साझा की।

# नर्सिंग कालिज में मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह मनाया गया

अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ नर्सिंग द्वारा मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के अवसर पर पांच दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नर्सिंग शिक्षकों और छात्राओं ने शहरी स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र (सामुदायिक चिकित्सा विभाग, जेएनएमसी के तहत संचालित) का दौरा किया और रोगियों के साथ बातचीत की और उन्हें मानसिक बीमारी के कारणों और ऐसी बीमारियों से उबरने के तरीकों और साधनों के बारे में जागरूक किया। छात्रों ने पीपीटी, फ्लैश कार्ड, पोस्टर और वीडियो के माध्यम से बताया कि मानसिक स्वास्थ्य में भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण शामिल है और यह हमारे सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके को प्रभावित करता है। यह यह निर्धारित करने में भी मदद करता है कि हम तनाव को कैसे प्रबंधित करते हैं, दूसरों से कैसे जुड़ते हैं और स्वस्थ विकल्प चुनते हैं। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य जीवन के हर चरण में महत्वपूर्ण है और इसे बढ़ावा देने के लिए मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों के प्रबंधन पर भी जोर दिया जाना चाहिए जो मानसिक दबाव और मानसिक बीमारी के कारण होते हैं।जेएनएमसी के ट्रॉमा सेंटर, ओपीडी में मानसिक विकारों और मानसिक रोगों से होने वाली बीमारियों पर एक नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य आम लोगों में मानसिक विकार और उनके प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैलाना था। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर एक पैनल चर्चा की अध्यक्षता करते हुए कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल प्रोफेसर फरहा आजमी ने मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने वाली थेरेपी के महत्व पर जोर दिया। डॉ. विजय लक्ष्मी वर्मा ने मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों के विभिन्न पहलुओं और उनके प्रबंधन के लिए उपलब्ध निःशुल्क सुविधाओं पर चर्चा की। सुश्री पामेला शालिनी जोसेफ ने मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए योग, ध्यान और कम से कम 8 घंटे की नींद के महत्व पर प्रकाश डाला। मनोचिकित्सा विभाग के डॉ. फैसल शान ने टेलीमानस सहित गैर सरकारी संगठनों की भूमिका पर चर्चा की, जो लोगों को मानसिक तनाव से निपटने में मदद करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से आत्महत्या के मुद्दे पर चर्चा की और लोगों को उनके भावनात्मक मुद्दों को कम करने में मदद करने में परिवार, साथियों और दोस्तों की भूमिका पर जोर दिया। सुश्री दीप्ति मिंज ने कार्यस्थल पर तनाव को कम करने के बारे में जानकारी दी जिससे हमारे मानसिक स्वास्थ्य और कार्य उत्पादन में सुधार होता है।

प्रो. आजमी ने बाद में धन्यवाद ज्ञापित किया।

# एएमयू के शिक्षकों द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय में पेपर प्रस्तुत

अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दर्शनशास्त्र विभाग के डॉ. अब्दुल शकील और डॉ. दीवान तसखीर खान ने विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. लतीफ हुसैन शाह काजमी के साथ 'महात्मा गांधी और इमाम खुमैनी के दृष्टिकोण से जीवन का अर्थ' विषय पर दिल्ली विश्वविद्यालय के फारसी विभाग द्वारा अल–मुस्तफा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ईरान की नई दिल्ली शाखा के सहयोग से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शोधपत्र प्रस्तुत किए। 'गांधी का अहिंसा दर्शन और आज की दुनिया में इसकी प्रासंगिकता' विषय पर एक पेपर प्रस्तुत करते हुए डॉ. शकील ने कहा कि महात्मा गांधी का अहिंसा का विचार केवल वास्तविक हिंसा का अभाव नहीं था, बल्कि जीवन का एक तरीका था जो विचारों, शब्दों, और कार्य को शामिल करता था जो सत्याग्रह के एक सिद्धांत का निर्माण करते हैं, जो सार्वभौमिक है और इसे राजनीति, सामाजिक सुधार और पारस्परिक संबंधों में लागू किया जा सकता है। डॉ. दीवान ने 'गांधी और खुमैनी के मानव अधिकारों के सिद्धांतः एक विश्लेषण' विषय पर बात की। खुमैनी को ईरान का गांधी बताते हुए उन्होंने कहा कि गांधी और इमाम खुमैनी दोनों ने अपने अभियान को अहिंसा के साथ आगे बढ़ाया और दोनों नेताओं ने अपने उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए धार्मिक सिद्धांतों का इस्तेमाल किया। गांधीजी का अहिंसा का दर्शन उनकी हिंदू मान्यताओं से गहराई से प्रभावित था, जबकि खुमैनी का नेतृत्व इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित था। प्रो. काजमी ने 'हमारे समय में महात्मा गांधी और इमाम खुमैनी के विचारों की प्रासंगिकता' विषय पर व्याख्यान दिया और दोनों महान नेताओं के बीच समानताएं उजागर कीं। उन्होंने उनके विचारों और सामाजिक–राजनीतिक गतिविधियों में बुनियादी सामान्य तत्वों पर प्रकाश डाला जिसमें भगवान में विश्वास और गीता और कुरान सहित पवित्र ग्रंथों से मार्गदर्शन, सत्य, ईमानदारी और अहिंसा आदि शामिल थे।

# संपूर्णानंद विवि के चारों द्वारों पर दिखेगी काशी की झलक,

## मेन हेरिटेज बिल्डिंग के सामने नहीं होगा झंडाय जल्द खुलेगा ज्योतिष परामर्श केंद्र

वाराणसी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के इंफ्रा स्ट्रक्चर और स्टडी सुविधाओं में आमूलचूल बदलाव होंगे। चारों प्रवेश द्वार को काशी के घाटों और मंदिरों के तर्ज पर डिजाइन किया जाएगा। ये काफी भव्य होगा। द्वार पर ही काशी की झलक देखने को मिलेगी। इसका रोड मैप तैयार किया जा रहा है। 234 साल पुराने मेन हेरिटेज बिल्डिंग के सामने से झंडा हटाया जाएगा। इसके दक्षिणी द्वार पर शिफ्ट किया जाएगा, जिससे मुख्य भवन की शोभा बनी रहे। छात्रों को पीने के लिए 24 घंटे RO वाटर मिलेगा। इसके लिए मशीनें लगाई जाएंगी। हॉस्टलों में स्मार्ट डस्टबीन रखे जाएंगे। साथ ही सड़कों और सीवर लाइन की मरम्मत होगी। ये फैसला आज कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा ने यूपी के मंत्री रविंद्र जायसवाल के साथ बैठक के बाद लिया। मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय में एक ज्योतिष परामर्श केंद्र भी खोला जाएगा। देश भर से काशी आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु अपने भाग्य फल के बारे में सभी जिज्ञासाएं शांत कर पाएंगे। यहां के केंद्र द्वारा लोगों को अच्छी से अच्छी सलाह दी जाएगी। कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि संपूर्णानंद परिसर में खुले ऑनलाइन संस्कृत ट्रेनिंग सेंटर के 10 कोर्स में अब तक देश भर से 700 लोगों ने अप्लाई किया है। इस कोर्स के द्वारा लोग घर बैठे ज्योतिष, कर्मकांड, वास्तुशास्त्र और बाकी ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। इनकी क्लासेज जल्द ही शुरू होने वाली हैं। कुलपति प्रो. शर्मा ने बताया कि संस्था के विकास और एडवांसमेंट के लिए काफी बारीकी से आज बैठक में मंथन किया गया। विकास की दृष्टि में अब आगे क्या किया जा सकता है, उस पर विचार किया जा रहा है। स्टडी पैटर्न को काफी बेहतर किया जाएगा। इस बैठक में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार राकेश कुमार, डॉ. कमलेश झा, छात्र कल्याण संकाय के अध्यक्ष प्रो. हरिशंकर पांडेय, प्रो. रमेश प्रसाद, दिनेश कुमार गर्ग, डॉ. मधुसूदन मिश्र, सुरक्षा अधिकारी अजय पांडेय, पार्षद प्रदीप राय आदि मौजूद थे।

# अपहरण कांड में पूर्व मंत्री अमरमणि नही हुआ पेश, कुर्क का नोटिस जारी

बस्ती,(यूएनएस)। कवियत्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में कुछ दिन पहले जेल से रिहा हुए पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। 22 वर्ष पहले व्यापारी धर्मराज के बेटे के बहुचर्चित अपहरण कांड में बस्ती की एमपी–एमएलए कोर्ट ने अमरमणि के खिलाफ बुधवार को कुर्क का नोटिस जारी कर दिया है। व्यापारी अपहरण कांड के मामले में अमरमणि के अधिवक्ता ने एनबीडब्लू आदेश को रिकॉल करने का प्रार्थनापत्र दिया गया था, जिसे आरोपी के उपस्थित न होने का कारण बताते हुए न्यायालय ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कुर्की की नोटिस जारी किया है। कोतवाली पुलिस को आदेश दिया गया है कि आरोपी की फरारी की उद्‌घोषणा समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाकर न्यायालय को सूचित करें। अगली सुनवाई के लिए 16 नवंबर तारीख तय की गई है। व्यापारी के बेटे के अपहरण केस में आरोपी पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के हाजिर होने की सुगबुगाहट पर पुलिस दिन भर अलर्ट रही न्यायालय के इर्दगिर्द पुलिस चहलकदमी करती रही। न्यायालय परिसर में जाने वालों की तलाशी हो रही थी। उसके खिलाफ न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। जिसे एक नवंबर को हाजिर होने का आदेश दिया गया था। उसके हाजिर न होने की दशा में शाम न्यायालय ने कुर्क का नोटिस जारी कर दिया है। इसमें एसपी बस्ती को विशेष टीम बनाकर गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया था। एसपी की तरफ से न्यायालय में बताया गया कि टीम बनाई गई है और गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

# यातायात जागरूकता रैली को डीएम-एसपी ने किया रवाना

बहराइच। जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश, दुघर्टनाओं में होने वाली मौत व गम्भीर रूप से घायल लोगों की संख्या में कमी लाये जाने के उद्देश्य से बुधवार को जागरूकता रैली को डीएम–एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीएम–एसपी ने वाहन का संचालन करते समय हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग करने की अपील की। डीएम–एसपी ने कहा कि यातायात का पालन करना जरूरी है। क्योंकि जिंदगी बहुत अनमोल है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी माता–पिता व परिवार के बड़े बुजुर्गों का कर्तव्य है कि बच्चों को अच्छे संस्कार के साथ–साथ यातायात नियमों का पालन करने की सीख भी दें। उन्होंने कहा कि प्राय मार्ग दुर्घटनाओं में घायल होने या मरने वाले व्यक्तियों में अधिकतर संख्या युवाओं की होती है। डीएम ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में तमाम तरह के सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं। व्यापक स्तर पर जन–जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को सुरक्षित ड्राइव करने तथा यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित भी किया।

# इतिहास विभाग में मुगल सम्राटों की उपेक्षित विरासत पर संगोष्ठी आयोजित

अलीगढ़। अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग और फारसी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में विद्वानों और विशेषज्ञों ने 'मुगल सम्राटों की उपेक्षित विरासतः सांस्कृतिक, साहित्यिक और स्थापत्य योगदान' पर विचार–विमर्श किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग

के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय इतिहास कांग्रेस के पूर्व सचिव प्रोफेसर सैय्यद जहीर हुसैन जाफरी ने भारतीय उपमहाद्वीप में धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक स्मारकों पर पाए गए ऐतिहासिक शिलालेखों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हालांकि इतिहासकारों ने मौजूदा मानक ग्रंथों और ऐतिहासिक दस्तावेजों का कल्पनाशील तरीके से उपयोग किया है, सूफी खानकाहों, दरगाहों और आधिकारिक और निजी संग्रहों में संरक्षित कई शिलालेखों, दस्तावेजों का रचनात्मक रूप से उपयोग किया जाना अभी भी बाकी है। उन्होंने कहा कि कभी–कभी किसी पुस्तक की आकस्मिक खोज ज्ञान के नए द्वार खोल सकती है जैसे कि मजलिस–ए–जहांगीरी शाही अदालतों की संस्कृति पर और विशेष रूप से जहांगीर और उनके विद्वान रईसों के अन्य धर्मों के विशाल और गहरे ज्ञान, विशेष रूप से ईसाई धर्म और इस्लाम के साथ इसके संबंध के बारे में विस्तार से प्रकाश डालती है। अपने स्वागत भाषण में, विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गुलफिशां खान ने अंतरधार्मिक संवाद के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि के रूप में सम्राट अकबर के शासनकाल पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि अकबर की धार्मिक नीति, जो 'सुलह–ए कुल' में निहित है, दक्षिण एशिया के इतिहास का एक बहुशोधित विषय है। लेकिन उनकी प्रबुद्ध नीति जिसे संस्कृत, ईसाई, यहूदी और अन्य धार्मिक ग्रंथों के फारसी में व्यापक अनुवादों से संदर्भित किया गया था, अभी तक संपादित, अनुवाद और प्रकाशित नहीं किया गया है। मुख्य अतिथि प्रो. अजरमी दुखत सफवी ने बताया कि फारसी भाषा में प्रवीणता ऐतिहासिक अनुसंधान और जांच की पहली शर्त है, जो मध्ययुगीन भारतीय के गहन विश्लेषण और व्यापक ऐतिहासिक शोध को सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कविता को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत के रूप में भी महत्व दिया क्योंकि यह कभी–कभी आम जनता की आवाज को प्रतिबिंबित करती है, जो मुख्यधारा के पारंपरिक स्रोतों में गायब है।

विशेष आमंत्रित सदस्य और कला संकाय के डीन प्रो. आरिफ नजीर ने अब्दुर रहीम खान–खाना और कवि तुलसीदास के बीच एक दिलचस्प संचार के बारे में बात की कि कैसे उनके काव्य आदान–प्रदान विभिन्न भाषाओं के कवियों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों को उजागर करते हैं और कैसे प्राचीन भारत के वसुधेव कुटुंबकम (एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य) के आदर्श वैश्विक एकजुटता और साझा आकांक्षाओं के सार को दर्शाते हैं। फारसी विभाग के अध्यक्ष और संयोजक प्रो. राना खुर्शीद ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

# यातायात माह का शुभारंभ, एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना

बस्ती। जिले में यातायात माह शुभारंभ अवसर पर बाइक व स्कूटी रैली निकाली गई। जिसे एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के शास्त्री चौक से निकाली गई। जिसमें महिला आरक्षी व पुलिस आरक्षी शामिल रहें। इस दौरान वे लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी कर रहे थें। यातायात माह शुभारंभ अवसर पर एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी ने कहा कि नवंबर माह हर साल की तरह यातायात माह के रूप में ट्रैफिक डिपार्टमेंट व पुलिस द्वारा मनाया जाता है। कहा कि इसमें जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है, इसमें इनफोर्समेंट भी किया जाता है, स्कूल में भी प्रोगाम किए जाएंगें। बताया कि पार्किंग के लिए स्थन निर्धारित किया जाएगा। इसके साथ ही नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने वालों का चालन भी किया जाएगा। दरअसल यूपी में नवंबर महिने में यातायात माह मनाया जाता है, इस दौरान नियमों को दरकिनार कर सड़कों पर गाड़ी चलाने वाले लोगों को जागरूक किया जाता है, साथ ही नियम तोड़ने वालों को सजा भी भुगतनी पड़ती है, इस माह में पुलिस के अधिकारी गांवों से लेकर शहरों, चौराहों, स्कूल और कॉलेज में जाकर सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाते हैं। इसके साथ ही सड़क दुर्घटना में मृत लोगों को श्रद्धांजलि भी दी जाती हैं। यातायात माह शुभारंभ अवसर पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली विनय पाठक, प्रभारी निरीक्षक महिला थाना अनीता यादव, भारी यातायात कामेश्वर सिंह सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को सुरक्षित यात्रा के बारे में समझा हैं, इसके साथ ही सड़क दुर्घटना को रोकना भी हैं।

# केन्द्र पर किसानों को नहीं होनी चाहिए असुविधा, डीएम ने दिया निर्देश,

## क्रय केंद्र का फीता काटकर जिले में धान खरीद की शुरुआत की

बहराइच। जिले में मूल्य समर्थन योजना के तहत 1 नवम्बर से प्रारम्भ होने वाली धान खरीद का जिलाधिकारी मोनिका रानी ने शुभारम्भ किया। डीएम ने कृषि उत्पादन मण्डी समिति परिसर सलारपुर पहुंचकर विधिवत पूजा–अर्चना की। उसके बाद फीता काटकर क्रय एजेन्सी खाद्य एवं रसद विभाग के धान क्रय केन्द्र का उद्‌घाटन किया।विकास खण्ड चित्तौरा के ग्राम पंचायत जोहरा से आए किसान हेमन्त वर्मा व कमोलिया निवासी किसान मंशाराम का स्वागत कर अपने सामने उनके उपज की तौल कराई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि किसी भी केन्द्र पर किसानों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। शासन की मंशानुरूप किसानों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। आवश्यकतानुसार क्रय केन्द्रों पर संसाधनों की बढ़ोत्तरी भी की जाए, ताकि किसानों के उपज की आसानी के साथ खरीदा जा सके। डीएम मोनिका रानी ने किसानों से अपील की अपनी उपज धान को सूखा कर क्रय केन्द्र पर लाएं। बिक्री के लिए शासन द्वारा निर्धारित पोर्टल एफसीएस डाट यूपी डाट जीओवी डाट इन पर अपना पंजीकरण अवश्य करा लें, ताकि तहसीलों द्वारा समय से सत्यापन की कार्रवाई की जा सके। डीएम ने बताया कि शासन की मंशानुरूप जनपद में धान की खरीद सुनिश्चित कराने के लिए सभी क्रय केन्द्रों के लिए नोडल अधिकारी भी नामित किए गए हैं।

# लखनऊ जिला कोर्ट में राहुल गांधी को लेकर सुनवाई,

## भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सावरकर पर की टिप्पणीय निचली अदालत ने खारिज की थी याचिका

लखनऊ। राहुल गांधी की वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी के खिलाफ आज एमपीएमएलए कोर्ट में लखनऊ के जज हरिवंश नारायण ने सुनवाई की। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सावरकर पर टिप्पणी की थी। इसको लेकर निचली अदालत में की गई याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन जिला जज अश्वनी कुमार त्रिपाठी ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। याचिकाकर्ता के वकील निपेन्द्र पांडेय ने बताया सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि दूसरे पक्ष की तरफ से कोई भी न्यायालय में मौजूद नहीं हुआ है। अगर आज कोई नहीं आता है तो फिर एक नोटिस और जारी की जाएगी। इसके बाद वाद में आगे की सुनवाई पर फैसला शुरू किया जाएगा।

एक अक्टूबर 2023 को याचिकाकर्ता नृपेंद्र पांडेय ने एमपी,एमएलए के विशेष एसीजेएम अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किए जाने की मांग वाली अर्जी दी थी। कोर्ट ने निगरानी याचिका पर सुनवाई के लिए राहुल गांधी को नोटिस जारी करते हुए एक नवंबर की तारीख तय की है। साथ ही पत्रावली को सुनवाई के लिए एमपी,एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट मे ट्रांसफर कर दिया है। याचिकाकर्ता नृपेंद्र पांडेय ने एमपी,एमएलए के विशेष एसीजेएम अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किए जाने की मांग वाली अर्जी दी थी। इसमें आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने सावरकर के खिलाफ 17 नवंबर 2022 को अकोला महाराष्ट्र में जानबूझकर टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। राहुल गांधी ने लगातार अंग्रेजों का पेंशनर, अंग्रेजों का नौकर, मददगार, अपनी रिहाई के लिए माफी मांगने वाला बताकर कई आरोप लगाए थे। निचली अदालत ने पहले इस अर्जी को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया, लेकिन बाद में परिवाद को क्षेत्राधिकार के बाहर का बताते हुए खारिज कर दिया था। निचली कोर्ट के इसी आदेश को निगरानी याचिका के जरिये चुनौती दी गई है।

# यातायात माह का हुआ शुभारंभ

उरई/जालौन, (यूएनएस)। जालौन में बुधवार से यातायात माह की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने यातायात माह वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही 17 बाइक चालकों को मुफ्त हेलमेट प्रदान किये। वहीं इस मौके पर केंद्रीय राज्यमंत्री ने 66 लाख की धनराशि से उरई को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ट्रैफिक लाइट और सीसीटीवी कैमरे दिए हैं। जिससे लोग यातायात का पालन सही तरीके से कर सकें। उरई कोतवाली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुये। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी। साथ ही कहा कि कोई भी व्यक्ति यातायात नियमों का उल्लंघन न करें। नियमों के पालन से ही जीवन सुरक्षित रहता है। इसलिए हमेशा यातायात का पालन करना चाहिये। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने अपने साथ हुई घटना के बारे में भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने सांसद रहते यातायात नियमों का उल्लंघन किया तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा उन्हें इसके बारे में अवगत कराया गया। जिसके बाद से ही वह यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने उरई शहर को बड़ी सौगात दी है। शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए उरई के तीन मुख्य चौराहे जिसमें भगत सिंह चौराहा, अंबेडकर चौराहा, जिला परिषद पर ट्रैफिक लाइट और सीसीटीवी कैमरे दिए हैं। जिससे लोगों से यातायात नियमों के बारे में सही से पालन कराया जा सके। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम अनुरागी, उरई विधायक गौरी शंकर वर्मा, माधौगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन, कालपी के सपा विधायक विनोद चतुर्वेदी तथा जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने भी लोगों को यातायात नियमों के बारे में जानकारियां दी। जिससे इसका सही से निर्वहन कर सके। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने यातायात वाहन को हरी झंडी दिखाकर तथा ट्रैफिक लाइटों का फीता काटकर शुभारंभ किया। साथ ही 17 बाइक चालकों को हेलमेट प्रदान किया। जिससे वह यातायात नियमों का सही से पालन कर सकें।

इस मौके पर जालौन की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा ने कहा कि शहर में प्रत्येक दिन यातायात माह पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही उनका मुख्य लक्ष्य लोगों को यातायात नियमों के बारे में सही से जानकारी देना है। उन्होंने कहा कि अभी शहीद भगत सिंह चौराहा, अंबेडकर चौराहा तथा जिला परिषद चौराहे पर ट्रैफिक लाइट और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अभी कुछ दिनों तक शहर में चालान नहीं किए जाएंगे। पहले लोगों को यातायात के बारे में और ट्रैफिक लाइट के बारे में जागरुक किया जाएगा। जिससे लोग इसका सही से पालन कर सकें। जागरुक होने के बाद लोगों के चालान यातायात का उल्लंघन करने पर काटे जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि यातायात माह में विशेष रूप से उन वाहनों की चेकिंग की जाएगी, जिनमें विधायक, सांसद जिला पंचायत और जिला अध्यक्ष लिखा होगा क्योंकि शहर में कई लोग जनप्रतिनिधियों के नाम पर गाड़ियों को चला रहे हैं।

# आईटीबीपी के जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा घर, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी

बांदा। जनपद में आज आईटीबीपी के जवान त्रिमोहन सिंह का पार्थिव शरीर बांदा जिले के चिल्ला के अतराहट गांव लाया गया। जवान का शरीर तिरंगे में लिपटे देख परिवार सहित गांव के लोगो की आंखे भर आई। जब जवान के पार्थिव शरीर को देखा तो पत्नी बेसुध हो गई और आखों से आंसू निकल रहे थे। उनकी पत्नी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। वही आज गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी गई। आपको बता दे की उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में तैनात आईटीबीपी के जवान त्रिमोहन सिंह 29 अक्टूबर को दोपहर के करीब दो बजे अपने आधा दर्जन साथियों के साथ नीलम घाटी में ड्यूटी कर रहा था तभी अचानक उसका पैर नीलम घाटी में फिसल गया जिसकी वजह से वह खाई में जा गिरा। जब तक जवान उस जगह तक पहुंच पाते तब तक जवान की मौत हो चुकी थी। वही जैसे ही यह खबर परिजनों को लगी तो गांव में मातम छा गया।

बड़े भाई ने बताया की मेरा भाई त्रिमोहन सिंह 1 महीने पहले छुट्टी में आया हुआ था। और वापस चला गया लेकिन यह नही पता था की वहा से यह खबर सुनने को मिलेगी। वही घटना सुनने के बाद जवान की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल ही। शाहिद जवान के दो लड़के थे पहला लड़का 7 साल का यश वर्धन और दूसरा चार वर्ष का रियांश था। इनकी शादी 10 साल पहले सतना के रायपुर में हुई थी। गांव में जैसे ही लोगो को जानकारी हुई तो गांव के लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए और अगल बगल के गांव के लोग भी इकट्ठा होना शुरू हो गए जवान का शरीर लगभग 3 बजे गांव जैसे ही पहुंचा तो लोगो ने भारत माता की जय के साथ नारा लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही पार्थिव का शरीर पत्नी के पास रखा गया तो वह बेसुध होकर गिर गई। गांव में जवान को अंतिम विदाई देने के लिए जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद, अशोक सिंह गौर, पूर्व विधायक दलजीत सिंह, प्रधान संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह आदि जन प्रतिनिधि समेत सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। गार्ड ऑफ आर्नर के साथ आईटीबीपी के जवानों ने सलामी देकर अंतिम विदाई दी। बड़े भाई वीरेंद्र सिंह ने मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार किया। इस दौरान कमांडेंट अमित कटियार व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

# दलित वोटरों को साधेगी बीजेपी, आज महासम्मेलन,

## 17 सांसद और 64 विधायकों के साथ लखनऊ पहुंचेंगे लोग, सीएम योगी होंगे शामिल

लखनऊ (यूएनएस)। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए BJP दलितों के बीच में पैठ बनाने के लिए गुरुवार को राजधानी लखनऊ में सबसे बड़ा दलित सम्मेलन करने जा रही है। यह सम्मेलन स्मृति उपवन में होगा, जहां लगभग 2 लाख दलितों की भीड़ इकट्ठा होने की संभावना है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ ही प्रदेश के 17 दलित सांसद और 64 विधायकों के साथ ही मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य भी शामिल होंगे। समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण ने कहा, अनुसूचित वर्ग सम्मेलन का यह 5वां कार्यक्रम है। अवध प्रांत का। इसमें अनुसूचित वर्ग के लोग शामिल होंगे। साथ ही मोदी जी को 5 साल फिर मिले इस पर भी बात होगी। भाजपा सबका साथ पर काम कर रही है। अनुसूचित वर्ग और महिलाओं के लिए अलग कार्यक्रम कर रही है। बीजेपी किसी एक व्यक्ति या समूह को वोट बैंक मानने की गलती नहीं करती है। हर घर में जाते हैं अपने विकास कार्यों के आधार पर। आज भारतीय जनता पार्टी का समर्थन पूरे देश में बढ़ा है। लखनऊ में होने वाले दलित सम्मेलन में बीजेपी के 17 अनुसूचित जाति से आने वाले सांसदों और 64 विधायकों को शामिल किया जाएगा। दरअसल घोसी उपचुनाव में मिली हार के बाद दलित वोट बैंक को लेकर भाजपा नेतृत्व चिंतित है। ऐसे में राजधानी लखनऊ में दलित सम्मेलन के जरिए भाजपा जहां एक तरफ दलितों को इकट्ठा करने के साथ सरकार की ओर से लाई गई योजनाओं के बारे में भी बताएगी। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों पर भी निशाना साधेगी। अवध क्षेत्र के इस सम्मेलन में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 2000 अनुसूचित जाति के लोगों को लाने का लक्ष्य दिया गया है। इसमें प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को शामिल करने के भी निर्देश दिए गए हैं। अवध क्षेत्र में कुल 82 विधानसभा क्षेत्र हैं। राजधानी लखनऊ में होने वाले अब तक के सबसे बड़े दलित सम्मेलन में प्रबुद्ध वर्ग से आने वाले लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। वहीं दलित समाज से आने वाले डॉक्टर–इंजीनियर्स, अफसरों, खिलाड़ियों, रिटायर्ड अफसरों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और लोक कलाकारों को भी शामिल किया गया है। इस सम्मेलन के जरिए दलित समाज के युवाओं पर भी फोकस रहेगा। दलित प्रतिभा सम्मेलन के जरिए प्रतिभावान विद्यार्थियों और युवाओं को सम्मानित करेंगे। युवाओं से बातचीत कर पता लगाएंगे कि वह पार्टी से क्या चाहते हैं, सरकार को उनके लिए क्या करना चाहिए।

बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए लगातार दलितों के बीच में अनेकों कार्यक्रम कर रही है। इससे पहले भी पूरे प्रदेश भर में बस्ती संपर्क एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसके तहत गांव–गांव तक इस अभियान को चलाया गया। बस्ती संपर्क अभियान के कार्यक्रम में भी सांसद–विधायकों को भी बस्तियों में भेजा गया है। और सभी से संपर्क स्थापित करने के साथ ही उनकी समस्याओं को भी सुनकर फिर रिपोर्ट तैयार करके मुख्यालय पर जमा किया गया।

# अब अयोध्या में होगी योगी कैबिनेट की बैठक, रामनगरी से बड़ा सियासी संदेश देने की तैयारी

लखनऊ,(यूएनएस)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में अगली कैबिनेट बैठक अयोध्या में की जाएगी। इस बैठक में अयोध्या के विकास और सुंदरीकरण के प्रस्ताव रखे जाएंगे। इसकी अभी तक कोई तारीख तय नहीं हुई है। लेकिन यह माना जा रहा है कि अयोध्या के दीपोत्सव के बाद कैबिनेट बैठक की जा सकती है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अयोध्या में होने वाली कैबिनेट बैठक के सियासी मायने भी तलाशे जाने लगे हैं। 29 जनवरी, 2019 को योगी 1.0 सरकार ने नया इतिहास रचते हुए प्रयागराज में कैबिनेट बैठक आयोजित की थी। ये बैठक संगम तट पर बसे टेंट सिटी में आयोजित हुई। गंगा–एक्सप्रेस वे के तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे बनाने का फैसला लिया। इसके साथ ही प्रयागराज के विकास से जुड़ी कई योजनाओं को हरी झंडी दी गई। सीएम योगी, तत्कालीन डिप्टी सीएम डॉ दिनेश शर्मा सहित सभी मंत्रियों ने बैठक से पूर्व संगम में स्नान किया। गौरतलब है कि जब उत्तराखंड यूपी का हिस्सा था तब कई बार लखनऊ के बजाए कैबिनेट की बैठक नैनीताल में भी होती थी। साल2019 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रयागराज में कैबिनेट बैठक आयोजित करके योगी 1.0 सरकार ने नया इतिहास तो गढ़ा साथ ही उस साल होने वाले आम चुनाव को लेकर बड़ा सियासी संदेश भी दिया था। अब जब साल 2024 के आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं तब लखनऊ के बाहर कैबिनेट बैठक आयोजित करने का फैसला लिया गया है। अगले साल 22 जनवरी को अयोध्या में राममंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन से पहले योगी सरकार तमाम गतिविधियों के जरिए माहौल सरगर्म रखना चाहती है। भव्य दीपोत्सव और फिर कैबिनेट बैठक की कवायद इसी की कड़ी मानी जा रही है।

# करवा चौथ पर सीमा के मायके से आया सामान,बोली– मेरी मां ने लहंगा–बिंदी–झुमके सब कुछ भेजा

नोएडा,। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर का भारत में पहला करवा चौथ है। वह इस व्रत को पूरे विधि–विधान से करेगी। इसके लिए सीमा हैदर ने वीडियो जारी किया है। सीमा ने कहा, मेरी मां ने मुझे करवा चौथ का पूरा सामान भेजा है। उन्होंने अपनी पसंद की हर चीज दी है। व्रत में जो कुछ भी जरूरी होता है, सब कुछ मुझे भेजा गया है। मैं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए यह व्रत रखूंगी। इसके साथ ही सीमा ने सचिन मीणा के साथ व्रत–पूजन का सारा सामान भी दिखाया। सीमा ने अपनी मां और मायके वालों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में अपने पति सचिन मीणा के साथ रह रही पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के लिए करवा चौथ का सामान वकील एपी सिंह की मां ने दिल्ली से भेजा है। सीमा ने एक वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर यह जानकारी लोगों को दी है। वकील एपी सिंह की मां को सीमा ने अपनी मां कहते हुए कहा कि वकील साहब का परिवार स्वस्थ रहे। साथ ही उसने भारत के सभी त्योहारों को काफी अच्छा बताया। सीमा का कहना है कि भारत के प्रत्येक त्योहार से उसको नई सीख मिल रही है। सीमा ने कहा, जय श्रीराम, राधे–राधे...। मैं बहुत खुश हूं कि मेरी अम्मा जी ने मेरे लिए करवा चौथ का सामान भेजा है। उन्होंने अपनी पसंद का सामान भेजा है। उन्होंने यह सब कुछ भेजा, इसके लिए उनका बहुत–बहुत धन्यवाद। मेरी मां स्वस्थ रहें, इसकी कामना करती हूं। मैं हद से ज्यादा खुश हूं। मैं सनातन धर्म के रीति–रिवाज के लिए यह व्रत रखूंगी। करवा चौथ का व्रत पूरे विधि–विधान से करूंगी। भारत बहुत अच्छा देश है। सभी त्योहार कुछ न कुछ संदेश देते हैं। सीमा ने कहा, मेरे परिवार वाले खुश रहें, स्वस्थ रहें। इसकी कामना करती हूं। पति सचिन की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखूंगी। भारतीय परंपरा सच में बहुत अच्छी है। भारत माता की जय, जय हिंद।

# आर्या 3 में मुझे अपने किरदार का नो-नॉनसेंस एटीट्यूड बहुत पसंद आया : माया सराओ

थ्रिलर ड्रामा आर्या 3 में माया बिश्नोई की भूमिका निभाने वाली एक्ट्रेस माया सराओ ने अपने और किरदार के बीच समानताओं पर

खुलकर बात की। शो में माया बिश्नोई आर्या (सुष्मिता) और हिना खान (सुगंधा गर्ग द्वारा अभिनीत) की सबसे अच्छी दोस्त है। अपनी भूमिका के बारे में बात करते हुए, माया ने कहारू मुझे उसका नो–नॉनसेंस एटीट्यूड पसंद आया और मैं समझ सकती हूं कि उसे अपने इस एटीट्यूड की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैंने जानबूझकर इस भूमिका को अपनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि यह रियल लाइफ में उस तरह से काम नहीं करता है। उन्होंने कहा, मैंने उन अनुभवों की कल्पना करने और जीने का प्रयास किया जिनका सामना माया ने कभी नहीं किया था, लेकिन माया नाम के पात्र ने ऐसा किया। उन्होंने आगे कहा, कभी–कभी, यह तय करना एक चुनौती होती है कि वह आंतरिक प्रेरणा कहां से प्राप्त की जाए। तीसरे सीजन में, आर्या की नजर ड्रग्स सप्लाई और ट्रांसपोर्टेशन पर है, लेकिन इला अरुण उसे रोक लेती है, जो खुद सप्लाई साइड में निर्विवाद रानी है। राम माधवानी द्वारा निर्मित और सह–निर्देशित और अमिता माधवनी, राम माधवानी, राम माधवानी फिल्म्स और एंडेमोल शाइन इंडिया द्वारा सह–निर्मित, आर्या 3 3 नवंबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर प्रसारित होगा।

# टमाटर के बाद अब यूपी में आसमान छू रहे प्याज के दाम, ग्राहक और दुकानदार दोनों हुए बेहाल

लखनऊ, (यूएनएस)। उत्तर प्रदेश में टमाटर के बाद अब प्याज त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डाल रहा है। खुदरा बाजार में प्याज की कीमतें पिछले एक सप्ताह में दोगुनी हो गई हैं, जो 30–35 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 60–80 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई हैं। पिछले चार महीनों में यह दूसरी बार है जब अगस्त के बाद प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं, जब प्याज 100 रुपए के पार पहुंच गया था। कुछ महीने पहले टमाटर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बाद इसने रसोई के बजट पर दबाव डाला है। प्याज की कीमतों में यह वृद्धि परिवारों और रेस्तरांओं के लिए कठिन बना रही है क्योंकि वे आगामी उत्सवों की तैयारी कर रहे हैं। व्यापारियों को चिंता है कि आने वाले महीनों में कीमतें बढ़ती रह सकती हैं। प्याज की ऊंची कीमतों के कई कारण हैं। थोक विक्रेताओं के अनुसार, इस साल की शुरुआत में खराब मौसम, लू और अनियमित बारिश के कारण प्याज की फसल खराब हो गई, जिसके परिणामस्वरूप थोक प्याज की कीमतें बढ़ गईं। सीतापुर मंडी के एक व्यापारी पप्पू सोनकर ने बताया, "वर्तमान में हमें स्थानीय बाजार में केवल 20–30 ट्रक प्याज मिल रहा है। हाल ही में पड़ोसी राज्य में प्याज व्यापारियों की हड़ताल से भी आपूर्ति बाधित हुई, जिससे कीमतों में बढ़ोतरी हुई। प्याज की बढ़ती कीमतों का असर उन परिवारों पर विशेष रूप से अधिक गंभीर है जो पहले से ही अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई रेस्तरां पहले ही सलाद की प्लेटों से प्याज हटा चुके हैं, जबकि स्ट्रीट फूड विक्रेताओं ने भी प्याज का उपयोग कम कर दिया है। आपको बता दें कि पुराने शहर में रेस्टोरेंट चलाने वाले नजमुल हसन ने कहा, प्याज की बढ़ती कीमतें हमारे कारोबार पर काफी दबाव डाल रही हैं। प्याज हमारे मांसाहारी व्यंजनों में एक महत्वपूर्ण घटक है और जब इसकी कीमतें बढ़ती हैं, तो यह हमारे भोजन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। बड़े रेस्तरां के विपरीत, हम सलाद और प्याज के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकते हैं, और इससे हमारे लिए लाभदायक बने रहना मुश्किल हो रहा है।

# 50 साल की हुई ऐश्वर्या राय, कैसे एक फिल्म से रातों-रात बन गई बॉलीवुड की क्वीन

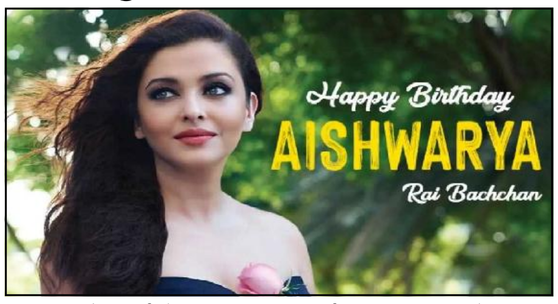


वर्ष 2000 ऐश्वर्या राय के सिने कैरियर के लिये अहम वर्ष साबित हुआ। इस वर्ष उनकी फिल्म 'जोश' प्रदर्शित हुयी जिसमें उन्होंने शाहरूख खान की बहन की भूमिका निभायी। इसके साथ ही ऐश्वर्या राय की 'हमारा दिल आपके पास है' और 'मोहब्बतें' जैसी कामयाब फिल्में भी प्रदर्शित हुयीं। वर्ष 2002 में ऐश्वर्या राय को शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के मशहूर उपन्यास. देवदास.पर बनी फिल्म में काम करने का अवसर मिला। संजय लीला भंसाली इसी नाम से बनी फिल्म में ..पारो.. के अपने किरदार से दर्शको का दिल जीत लिया। इस फिल्म के लिये दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित की गयीं। इस फिल्म को कांस फिल्म समारोह में विशेष स्क्रीनिंग के दौरान दिखाया भी गया।

वर्ष 2003 में ऐश्वर्या ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रख दिया और फिल्म 'दिल का रिश्ता' का निर्माण किया लेकिन यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नही रही। वर्ष 2004 में ऐश्वर्या को गुरिन्दर चड्ढा की अंग्रेजी फिल्म 'प्राइड एंड प्रीजुडिस' और राज कुमार संतोषी की फिल्म 'खाकी' में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का अवसर मिला। फिल्म में ऐश्वर्या ने अपने सिने कैरियर में पहली बार नेगेटिव किरदार निभाया जो सिने दर्शको को काफी पसंद आया। वर्ष 2004 ऐश्वर्या के सिने कैरियर का उपलब्धियों वाला वर्ष साबित हुआ। उस वर्ष उनके ऐश्वर्य को देखते हुये लंदन के सुप्रसिद्ध मैडम तुसाद म्यूजियम में उनका मोम का पुतला लगाया गया। इसी साल अमरीका की सुप्रसिद्ध पत्रिका टाइम मैगजीन ने विश्व की 100 प्रभावशाली हस्तियों में ऐश्वर्या का नाम शामिल किया।वर्ष 2006 में ही ऐश्वर्या ने यश चोपड़ा के बैनर तले बनी फिल्म धूम के सीक्वेल 'धूम 2' में काम किया। इस फिल्म में उन्होंने एक बार फिर से नकारात्मक किरदार निभाया और दर्शको का भरपूर मनोरंजन किया। वर्ष 2009 में फिल्म क्षेत्र में ऐश्वर्या राय के उल्लेखनीय योगदान को देखते हुये उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभिषेक बच्चन के साथ शादी के बाद अपने पारिवारिक दायित्व को देखते हुये ऐश्वर्या ने फिल्मों में काम करना काफी कम कर दिया। वर्ष 2010 में प्रदर्शित फिल्म 'गुजारिश' में काम करने के बाद ऐश्वर्या फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गयीं। ऐश्वर्या ने वर्ष 2015 में प्रदर्शित फिल्म जज्बा से इंडस्ट्री में कमबैक किया है।

ऐश्वर्या की वर्ष 2016 में सरबजीत और ऐ दिल है मुश्किल प्रदर्शित हुयी है जिसे टिकट खिड़की पर कामयाबी मिली। वर्ष 2018 में ऐश्वर्या की फिल्म फन्ने खान प्रदर्शित हुयी है। इसके बाद ऐश्वर्या राय ने कुछ समय के लिये ब्रेक ले लिया। वर्ष 2022 में ऐश्वर्या राय की पोन्नियिन सेलवन और वर्ष 2023 में पोन्नियिन सेलवन 2 जैसी सुपरहिट फिल्में प्रदर्शित हुयी

# अब्बास-मस्तान की एक्शन थ्रिलर फिल्म में काम करेंगे सनी देओल

बॉलीवुड अभिनता सनी देओल निर्देशक जोड़ी अब्बास–मस्तान की एक्शन थ्रिलर फिल्म में काम करते नजर आ सकते हैं। गदर 2 की सफलता के बाद सनी देओल,आमिर खान के प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म श्लाहौर 1947श में काम कर रहे हैं, जिसका निर्देशन राजकुमार संतोषी करेंगे। बताया जा रहा है कि सनी देओल, इसके अलावा अब्बास–मस्तान के साथ एक्शन थ्रिलर फिल्म करते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म को विशाल राणा प्रोड्यूस कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब्बास मस्तान– सनी देओल के बीच एक लंबे समय से एक प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत चल रही थी, अब फाइनली चीजें सही जगह पर हैं। ये एक बिग स्केल एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जो ट्विस्ट एंड टर्न से भरपूर होगी।

मेकर्स ने सनी देओल स्टारर एक्शन थ्रिलर फिल्म का प्री–प्रोडक्शन वर्क शुरू कर दिया है। यह फिल्म साल 2024 की शुरुआत में फ्लोर पर जाएगी।

# सलमान ने मुझसे कहा था कि अगर रेस 3 का हिस्सा बनना है तो शर्ट उतारनी होगी : बॉबी देओल

अपनी अपकमिंग फिल्म एनिमल की रिलीज का इंतजार कर रहे एक्टर बॉबी देओल ने साझा किया है कि बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने उनसे कहा था कि अगर वह रेस 3 का हिस्सा बनना हैं तो अपनी शर्ट उतारनी होगी। बॉबी, जिन्हें अक्सर सोशल मीडिया पर लॉर्ड बॉबी कहा जाता है, निर्देशक–निर्माता करण जौहर द्वारा होस्ट किए जाने वाले लोकप्रिय चौट शो कॉफी विद करण के दूसरे एपिसोड का हिस्सा बने। बॉबी देओल ने कहारू सलमान ने मुझसे कहा था कि देख जब मेरा करियर ठीक नहीं चल रहा था, मैं तेरे भाई की पीठ पर चढ़ गया था, मैं आगे बढ़ा, मैं संजय दत्त की पीठ पर चढ़ गया। मैं आगे बढ़ा। हम एक–दूसरे को मामू कहते हैं, तो मैंने उसको बोला, मामू, तो मुझे तेरे पीठ पर चढ़ने दे ना... सलमान को मेरी ये बात याद थी। कुछ सालों बाद मेरे पास उनका फोन आया। उसने मुझसे कहा, मामू शर्ट उतारेगा। मैंने झट से बोला, हां मामू मैं कुछ भी करूंगा। बस इस तरह मुझे फिल्म रेस 3 मिली। कॉफी विद करण सीजन 8 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध है।

अवध की आवाज हिन्दी दैनिक, प्रकाशक ,मुद्रक व स्वामी,अनिल कुमार सिंह द्वारा स्काई लाइन प्रिन्टर्स,119/23 खन्दारी लेन, लालबाग, लखनऊ उ0प्र0 से मुद्रित तथा डी–97/3 व 7,सेक्टर–7, इन्दिरा नगर,लखनऊ,उ0प्र0 से प्रकाशित। सम्पादक अनिल कुमार सिंह फोन : 0522–4340954 मो0–7905407289, Email: avadhkiaawaz@gmail.com
R.N.I.- UPHIN/2012/45127
नोट : समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादोंका न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।